कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57 डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 वर्ष-80 अंक - 7 मूल्य-रु. 12/- कुल पृष्ठ-16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

धनतेरस एवं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

कृषक जगत के सुधी पाठकों, विज्ञापनदाताओं, प्रतिनिधियों एवं शुभचिंतकों को धनतेरस एवं दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

\- कृषक जगत परिवार

प्रधानमंत्री ने किया

धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ

नई दिल्ली (कृषक जगत)। पूसा, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएँ कीं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी भी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने दो नई योजनाएँ शुरू कीं

- **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** आकांक्षी जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को जोड़कर कृषि विकास को गति देने के लिए।
- **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन:** देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और आयात घटाने के लिए।

उन्होंने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 परियोजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास किया, जिससे रु. 42,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रोसेसिंग यूनिट्स विकसित होंगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, यूरिया रु. 266 और डीएपी रु. 1350 में उपलब्ध है; सरकार ने बढ़ी लागत का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। कृषि यंत्रों पर जीएसटी घटाया गया है।

एमएसपी में वृद्धि: गेहूं रु. 160, चना रु. 200+, मसूर रु. 300, सरसों रु. 250, कुसुम रु. 600 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। श्री चौहान ने कहा किसान सम्मान निधि से अब तक रु. 3.90 लाख करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे। किसान क्रेडिट कार्ड से रु. 10 लाख करोड़ ऋण और रु. 1.62 लाख करोड़ ब्याज सब्सिडी दी गई। वहीं फसल बीमा योजना के तहत रु. 1.83 लाख करोड़ मुआवजा मिला। देशभर में 52 लाख किसान एफपीओ के शेयरहोल्डर बने, और 1100 एफपीओ रु. 15,000 करोड़ से अधिक टर्नओवर तक पहुँचे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से शामिल हुए।

प्रदेश में 138 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होगी रबी बोनी

96 लाख हेक्टेयर में होगा गेहूं

(अतुल सक्सेना)

भोपाल (कृषक जगत)। प्रदेश में इस वर्ष रबी 2025-26 में 138 लाख 85 हजार हेक्टेयर में रबी फसलें लगाई जाएंगी। गत वर्ष 140 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली गई थीं। दूसरी तरफ अक्टूबर आधा बीत गया है, लेकिन खरीफ की कटाई अभी चल रही है, इस कारण रबी की बुवाई की गति धीमी है। धान के खेतों में फसल खड़ी है, जहां तक इस रबी बुवाई का सवाल है तो जबलपुर संभाग में सबसे अधिक तथा शहडोल संभाग में सबसे कम बोनी का लक्ष्य कृषि विभाग ने रखा है।

कृषि विभाग के मुताबिक इस वर्ष राज्य में 138 लाख 85 हजार हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 96 लाख 81 हजार हेक्टेयर में की जाएगी। गत वर्ष गेहूं 101 लाख हेक्टेयर में बोया गया था। जानकारी के मुताबिक राज्य में

दलहनी फसलों के तहत मुख्य रूप से चने की बोनी 17.28 लाख हेक्टेयर में, मसूर 6.35 तथा मटर 3.30 लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी। इसी प्रकार तिलहनी फसलों में मुख्यत: सरसों की बुवाई 12.22 लाख हेक्टेयर में तथा अलसी 1.20 लाख हेक्टेयर में ली जाएगी।

(शेष पृष्ठ 9 पर)

वर्ष 2025-26 में प्रमुख रबी फसलों का बुवाई लक्ष्य (लाख हे. में)

फसल	लक्ष्य
गेहूं	96.81
जौ	0.34
चना	17.28
मसूर	6.35
मटर	3.30
सरसों	12.22
अलसी	1.20
गन्ना	1.32

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

पराली प्रबंधन पर किसानों को जागरुक करना बेहद जरूरी : श्री चौहान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। पराली प्रबंधन को लेकर नई दिल्ली, कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त रूप से बैठक हुई। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री मजिंदर सिंह सिरसा वर्चुअली शामिल रहे। बैठक में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने और धान पराली के बेहतर उपयोग सहित किसानों के बीच जागरुकता, वित्तीय सहायता, प्रभावी निगरानी, फसल प्रबंधन व विविधिकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह को अपने-अपने राज्यों में पराली प्रबंधन की स्थिति से अवगत करवाया साथ ही बताया कि पूरी सक्रिता और सतर्कता के साथ पराली प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पूरा विभाग गंभीरतापूर्वक कार्य में जुटा है।

बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका व्यापक असर हुआ है।

राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों में पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जनजागरुकता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों व नोडल अधिकारियों की भी भागीदारी यदि सुनिश्चित की जाए, तो और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में फसल प्रबंधन, सीधी बुवाई, विविधिकरण, राज्यों द्वारा कार्य योजना धनराशि का उचित उपयोग, प्रभावी निगरानी साथ ही साथ लक्ष्यबद्ध रूप से व्यावहारिक योजनाओं के निर्माण को लेकर भी चर्चा की। बैठक में कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होगा

मतगणना 14 नवंबर को होगी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में होगी - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। सभी सीटों की मतगणना एक साथ 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में पुलिस अवलोकक तैनात किए जाएंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव समय पर पूरे होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं।

ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार, 9 नई वस्तुएं जुड़ीं

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि मंत्रालय ने 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। यह महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है। जोड़ी गई 9 नई वस्तुएं इस प्रकार हैं-

● ग्रीन टी ● चाय ● अश्वगंधा की सूखी जड़ें ● सरसों का तेल ● लैवेंडर तेल ● मेंथा ऑयल ● वर्जिन जैतून का तेल ● लैवेंडर के सूखे फूल ● ब्रोकन राइस।

सोयाबीन और मक्का के दाम गिरे, किसानों को एमएसपी से कम कीमतें

नई दिल्ली (कृषक जगत)। खरीफ 2025 में प्रमुख फसलों सोयाबीन और मक्का की कीमतें कमजोर रहीं। बुवाई में कमी और एमएसपी बढ़ने के बावजूद किसानों को दोनों ही फसलों के लिए समर्थन मूल्य से कम दाम मिले।

सोयाबीन की स्थिति

कृषि मंत्रालय के अनुसार, खरीफ 2025 में सोयाबीन का रकबा घटकर 120.32 लाख हेक्टेयर रह गया (पिछले साल 126.04 लाख हेक्टेयर)। सरकार ने एमएसपी रु. 5,328 प्रति क्विंटल तय किया है, परंतु सितंबर में देशभर की मंडियों में औसत भाव केवल रु. 4,617 प्रति क्विंटल रहे - यानी करीब 11.6 प्रतिशत गिरावट।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भाव 7-15 प्रतिशत तक गिरे, जबकि तमिलनाडु में रिपोर्टिंग त्रुटि जैसी असामान्य उछाल (रु. 8,562/क्विंटल) दर्ज हुई।

कमज़ोर अंतरराष्ट्रीय मांग, सोयाबीन तेल व खली के दामों में गिरावट और खराब गुणवत्ता वाली फसल ने बाजार को दबाव में रखा। किसानों को एमएसपी और वास्तविक दाम के बीच करीब रु. 1200 प्रति क्विंटल का घाटा झेलना पड़ा।

मक्का बाजार पर दबाव

सितंबर 2025 में मक्का का औसत भाव रु. 2,115 प्रति क्विंटल रहा, जो अगस्त से 9 प्रतिशत और पिछले साल से 10 प्रतिशत कम है।

खरीफ 2025 में मक्के की बोआई 18 प्रतिशत बढ़कर 94.62 लाख हेक्टेयर तक पहुंची, जिससे भारी आवक और बढ़ी आपूर्ति ने दाम नीचे खींचे।

मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भाव 18-21 प्रतिशत तक गिरे। हालांकि इथेनॉल उत्पादन की मांग बढ़ी है, परंतु DDGS जैसे सह-उत्पाद ने पशु आहार में मक्के की पारंपरिक मांग को कम किया है।

आगे की दिशा

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में कीमतें इस पर निर्भर करेंगी कि-

● सरकार एमएसपी पर कितनी खरीद करती है। ● इथेनॉल संयंत्र मक्का की खरीद कितनी बढ़ाते हैं, और ● अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल व अनाज की कीमतें कैसी रहती हैं।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल बेचने का सही समय चुनें, भंडारण और अनुबंध खेती जैसे विकल्प अपनाकर नुकसान कम करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

ICL
ICL – पोषण जो लाए
रंग, तीखापन और मुनाफ़ा!
ICL के उन्नत पोषण समाधानों के साथ पाएँ
हर फसल में मजबूती, संतुलन और भरपूर उत्पादन।
आज ही हमारे टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने नज़दीकी ICL डीलर/रीटेलर से ICL के प्रोडक्ट्स ख़रीदें।
FertiFlow Grow
FertiFlow Bloom
Polysulphate
POLYSULPHATE PREMIUM
FertiFlow Tomato I
NPK 16 11 32
FertiFlow Tomato II
www.icl-growingsolutions.com/en-in/
Toll Free no. 1800 210 3031
CONNECT US

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

कृषक जगत

संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर और कोई पाप नहीं।

- स्वामी विवेकानन्द

किसानों की मेहनत, बाजार की बेरुखी और प्रसंस्करण की जरूरत

हर साल बरसात के मौसम में हरी सब्जियों के साथ प्याज और लहसुन की कीमतें तेज़ी से बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि आम उपभोक्ता गर्मियों के दिनों में इनका संग्रह कर लेते हैं। लेकिन यदि प्याज को उचित वातावरण और तापमान में संग्रहित नहीं किया जाए तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब बाजार में आवक कम होती है तो कीमतें बढ़ती हैं और किसान उम्मीद से मंडियों का रुख करते हैं। इस साल परिदृश्य बिल्कुल उलट गया। मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच और अन्य मंडियों में प्याज-लहसुन के भाव बरसात के दिनों में बढ़ने के बजाय गिर गए। दो-तीन रुपये किलो की दर पर बिकना किसानों के लिए गहरी निराशा का कारण बना। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनकी आय के साधन पहले से ही सीमित हैं, यह हालात किसी तुषारापात से कम नहीं रहे।

यह घटना नई नहीं है। इसी साल फरवरी-मार्च में टमाटर के दामों में भारी गिरावट से किसान इतने हताश हुए कि उन्होंने टमाटर को मंडियों तक ले जाने के बजाय खेतों में ही सड़ने दिया। जब भी किसी फसल की आवक मांग से अधिक हो जाती है, कीमतें गिरना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि यदि उत्पादन अधिक हो जाए तो किसान नुकसान से कैसे बचें? चूंकि देश के 85 प्रतिशत से अधिक

किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, वे मांग का अनुमान लगाकर उत्पादन नहीं कर सकते। ऐसे में अधिशेष उत्पादन का प्रसंस्करण ही एकमात्र व्यवहारिक उपाय है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है, लेकिन प्रसंस्करण का स्तर मात्र 2 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि हर साल करोड़ों टन उपज बर्बाद हो जाती है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शुरू की हैं। 28 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 394 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट और 536 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। फिर भी, जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रगति न होने के कारण किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचने से वंचित है।

नीतिगत प्राथमिकता की जरूरत

यह स्वीकार करना होगा कि गेहूं, धान, दलहन जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था है, लेकिन फल और सब्जियों को इसके दायरे में लाना संभव नहीं है। इसलिए किसानों के हितों की रक्षा के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता देना ही एकमात्र रास्ता है। यदि प्रसंस्करण क्षमता मजबूत हो तो अधिशेष उत्पादन भी लाभ में बदल सकता है। इससे किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद मिलेंगे और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना और विस्तार को उच्च प्राथमिकता दें। यदि हम फसल बर्बादी को रोकने और किसानों को लागत से ऊपर कीमत दिलाने में सफल होते हैं तो यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि किसानों की आर्थिकी को स्थायी आधार भी प्रदान करेगा। प्याज और लहसुन के मौजूदा संकट ने हमें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था खड़ी करना समय की मांग है।

आमदनी में पारंपरिक खेती से आगे नहीं प्राकृतिक खेती

न ही आहार विविधता में दिलाती है खास बढ़त

● सचिन श्रीवास्तव

देश में खेती-किसानी के तरीकों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर आधारित पारंपरिक खेती को जहां अधिक उत्पादन देने वाला माना जाता है, वहीं प्राकृतिक खेती को टिकाऊ, स्वास्थ्यकर और पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है। लेकिन हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने इस बहस को नए सिरे से खोल दिया है। अध्ययन में पाया गया है कि प्राकृतिक खेती न तो आमदनी के मामले में पारंपरिक खेती से आगे है और न ही आहार विविधता में कोई खास बढ़त दिलाती है। बल्कि यह वर्ग, जाति और शिक्षा के आधार पर एक अलग सामाजिक संरचना को सामने लाती है।

यह अध्ययन 'रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट की ओर से किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड को शामिल किया गया। अध्ययन का उद्देश्य था- प्राकृतिक खेती का पोषण पर क्या असर है और यह व्यापक सामाजिक-आर्थिक संरचना में किस तरह शामिल होती है।

अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक खेती करने वाले परिवारों के पास खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता अधिक है। वे अपने लिए भोजन का अधिकांश हिस्सा खुद पैदा कर लेते हैं और बाज़ार पर कम निर्भर रहते हैं। इसके उलट पारंपरिक किसान अधिकतर खाद्य सामग्री के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं।

आम धारणा यह रही है कि प्राकृतिक खेती करने वाले परिवार ज्यादा पोषणयुक्त भोजन करते होंगे। लेकिन अध्ययन ने यह मिथक तोड़ दिया। दोनों ही समूहों के खानपान में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला। यहाँ तक कि आहार विविधता पारंपरिक खेती करने वालों में थोड़ी अधिक पाई गई, क्योंकि वे बाज़ार से अलग-अलग खाद्य वस्तुएँ खरीद लेते हैं।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हरित खाद, जैविक तरल खाद, वर्मी-कम्पोस्ट जैसी तकनीकों को प्राथमिकता देते हैं। यह टिकाऊ खेती का उदाहरण है। लेकिन अध्ययन में यह भी पाया गया कि पारंपरिक किसान भी अब इन तरीकों को अपनाने लगे हैं- जैसे शून्य जुताई, न्यूनतम जुताई, हरी खाद और जैव-उर्वरक का उपयोग। यानी दोनों पद्धतियों के बीच का अंतर धीरे-धीरे धुंधला होता जा रहा है।

इस बारे में एग्रोइकोलॉजी विशेषज्ञ और अध्ययन दल के सदस्य अंशुमन दास प्राकृतिक और पारंपरिक खेती की तुलना कोई काले-सफेद जैसी स्थिति नहीं है। दोनों के बीच की रेखाएं धुंधली हैं। जरूरत है गहराई से समझने की कि टिकाऊ और लाभकारी खेती कैसे आगे बढ़ाई जाए।

देश में रासायनिक और प्राकृतिक खेती के बीच जारी बहस को एक नए अध्ययन ने नया मोड़ दिया है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक खेती न तो आय में पारंपरिक खेती से आगे है, न ही आहार विविधता में। बल्कि यह वर्ग, जाति और शिक्षा के आधार पर एक नई सामाजिक संरचना को रेखांकित करती है, जहाँ टिकाऊपन तो है, पर समानता नहीं।

यह है फर्क

हालांकि एक फर्क यह सामने आया कि पारंपरिक खेती करने वाले किसान कृषि के अलावा अन्य आय स्रोतों- जैसे सरकारी या निजी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती करने वाले पूरी तरह कृषि पर टिके रहते हैं।

युवाओं में पारंपरिक खेती प्रचलित

अध्ययन में सामने आया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले अधिकतर किसान उम्र में बड़े, शिक्षित और ऊंची जाति से जुड़े होते हैं। आंकड़ों के अनुसार, प्राकृतिक खेती करने वालों में 46-61 वर्ष आयु वर्ग के 38.67 प्रतिशत और 62 वर्ष से ऊपर के 18.67 प्रतिशत किसान शामिल थे। इसके उलट पारंपरिक खेती करने वाले 30-45 वर्ष आयु वर्ग के 48 प्रतिशत किसान थे, यानी पारंपरिक खेती अपेक्षाकृत युवा किसानों के बीच अधिक प्रचलित है। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती अधिकतर पुरुषों द्वारा की जाती है, जबकि पारंपरिक खेती में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई।

सामान्य और एसटी में प्राकृतिक, ओबीसी-एससी में पारंपरिक खेती ज्यादा प्रचलित

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि प्राकृतिक खेती सामान्य वर्ग की जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में अधिक प्रचलित है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जातियों (एससी) में पारंपरिक खेती अधिक लोकप्रिय है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई क्षेत्रों में आदिवासी आबादी पारंपरिक रूप से बिना रसायन वाली खेती करती रही है, इसलिए उनकी संख्या प्राकृतिक खेती में अधिक दिखती है।

उच्च शिक्षित कर रहे प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती करने वालों में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या भी अधिक है। इसका अर्थ है कि पढ़ाई-लिखाई का स्तर खेती की पद्धति चुनने में अहम भूमिका निभाता है। यह बात नीति-निर्माताओं के लिए खास महत्व रखती है क्योंकि शिक्षा और जागरूकता खेती में बदलाव का रास्ता खोल सकते हैं।

आय में कोई बड़ा अंतर नहीं

अध्ययन में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्राकृतिक और पारंपरिक खेती के बीच आय में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला।

- हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक किसानों की औसत सालाना आय 2,53,600 रुपए रही, जबकि प्राकृतिक किसानों की 2,52,453 रुपए।
- राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पारंपरिक किसानों की आय क्रमशः 1,60,500 रुपए और 1,13,600 रुपए रही, जबकि प्राकृतिक खेती वालों की आय 1,49,533 रुपए और 98,093 रुपए रही।
- पश्चिम बंगाल और झारखंड में दोनों वर्गों की आय लगभग समान रही।

मृदा स्वास्थ्य व टिकाऊ खेती के लिए करें जैव उर्वरकों का प्रयोग

- अनिल कुमार सिंह • सिद्धार्थ नायक
- ऋचा सिंह • अक्षता तोमर
- दिनेश कुमार सिंह

कृषि विज्ञान केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

aksjnkvv01@gmail.com

जैव उर्वरक जीव आधारित खादें हैं। ये लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमण्डल में पहले से विद्यमान नाईट्रोजन को स्थिरीकृत कर फसल को उपलब्ध कराती हैं तथा मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को पानी में घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार रासायनिक खाद की आवश्यकता सीमित हो जाती है। जैव खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलो ग्राम नाईट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है। जिससे फसलोत्पादन 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। अतः रासायनिक उर्वरकों को थोड़ा कम प्रयोग करके बदले में जैव उर्वरकों का प्रयोग करके फसलों की भरपूर उपज प्राप्त की जा सकती है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की पूरक तो हैं ही साथ ही ये उनकी उपयोग क्षमता भी बढ़ाती हैं। फास्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है साथ ही साथ फास्फोरस प्रदायी जैव उर्वरक यथा स्यूडोमोनास, बेसिलस, माइकोराइजा भूमि में उपस्थित अघुलनशील स्फुर को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। मुख्यतः जैव उर्वरक दो प्रकार के होते हैं - नत्रजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक तथा फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक। इसके अतिरिक्त पोटैशियम व जिंक प्रदायी जैव उर्वरकों के प्रयोग से पोटैशियम व जिंक की उपलब्धता बढ़ती है व खेती की लागत भी कम होती है।

फसलों के लिये राइजोबियम जैव-उर्वरक

राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। राइजोबियम जैव उर्वरक वातावरण की नाइट्रोजन को फसल के साथ सहभागिता/सहजीवी रूप में अवशोषित कर भूमि में स्थिर करते हैं। अंकुरण के उपरांत ये जीवाणु, पौधों की जड़ों में प्रविष्ट होकर छोटी-छोटी गांठों का निर्माण करते हैं और वायुमंडलीय नत्रजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इन जीवाणुओं का एक विशेष व्यवहार होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दलहनी फसलों के लिये अलग-अलग प्रजाति के जीवाणु आवश्यक होते हैं। जीवाणु की एक प्रजाति जो किसी फसल में जड़ ग्रथियां बनाने में सक्षम है, वह दूसरी फसल में जड़ ग्रंथियां नहीं बना सकता।

खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उपज में वृद्धि तो होती है परंतु असंतुलित एवं अव्यवस्थित प्रयोग से मृदा की उर्वरता तथा संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिये रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग की कृषि में सम्भावनायें बढ़ रही हैं। जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसल को पोषक तत्वों की आपूर्ति होने के साथ मृदा उर्वरता भी स्थिर बनी रहती है तथा लागत भी कम लगती है। जैव उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के साथ करने से रासायनिक उर्वरकों में निहित पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ती है जिससे फसलोत्पादन में वृद्धि होती है।

एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक

यह असहजीवी जीवाणु है जो पौधों की जड़ों की सतह में स्वतंत्र रुप से रहते हुये वायुमण्डलीय नत्रजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये जीवाणु कुछ विशेष पादप वृद्धि नियामक पदार्थों जैसे-जिबरेलीन का स्त्राव करते हैं जो फसल की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही कुछ एण्टीबायोटिक रसायन उत्सर्जित करते हैं जिससे फसल में लगने वाले भूमि जन्य रोग व वायरस रोगों से फसल का बचाव होता है। एजोटोबैक्टर के उपयोग से 20-40 किग्रा नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष तक फसल को प्राप्त होती है।

नील हरित काई (शैवाल)

पानी की सतह पर नीले-हरे रंग की यह शैवाल, सूर्य प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाकर, वायुमण्डल की नत्रजन को स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराती है। इनके द्वारा 20-30 कि.ग्रा. नत्रजन प्रति हेक्टेयर तक फसल को प्राप्त होती है जिससे 10-15 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि देखी गयी है। एक एकड़ खेत में 4 कि.ग्रा. सूखी नील-हरित शैवाल की आवश्यकता पड़ती है इसके विकास के लिये खेत में 7-8 से.मी. पानी भरा रहें।

फास्फोरस प्रदायी जैव उर्वरक (पीएसबी)

फास्फोरस प्रदायी जैव उर्वरक स्यूडोमोनास, बेसिलस, माइकोराइजा भूमि में उपस्थित अघुलनशील स्फुर को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः स्फुर की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे-सुपर फास्फेट, डीएपी का केवल 20 प्रतिशत भाग ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो पाता है। स्फुर प्रदायी जैव उर्वरक, भूमि में उपस्थित 80 प्रतिशत अघुलनशील स्फुर को घुलनशील एवं गतिशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास अच्छा होने से उत्पादन में 8-10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है।

जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे करें

बीज निवेशन (बीजोपचार)- 20 से 40 कि.ग्रा. बीज के लिये राइजोबियम का एक पैकेट (200 ग्राम) पर्याप्त है इस हेतु 50-100 ग्राम गुड़/शक्कर को 500 मिली पानी में घोल बनाकर उसे गर्म करते हैं व ठंडा कर इसमें जैव उर्वरक को घोलकर, बीज के साथ मिलायें। जब राइजोबियम व पीएसबी को एक साथ उपयोग करना हो तब राइजोबियम का एक पैकेट व पीएसबी के दो पैकेट उपयोग करें। बीज को छाया में सुखाकर उसी दिन बुवाई कार्य करें।

जड़ उपचार - जैविक खाद का प्रयोग जड़ोपचार हेतु रोपाई वाली फसलों में करते हैं। 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 -25 लीटर पानी में घोल बनायें। एक हेक्टेयर के लिये पर्याप्त पौध की जड़ों को 25-30 मिनट तक उपरोक्त घोल में डुबोकर रखें। उपचारित पौध को छाया में रखें तथा यथाशीघ्र रोपाई कर दें।

मृदा उपचार - एक हेक्टेयर भूमि के लिये 200 ग्राम वाले 25 पैकेट जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। 50 किलोग्राम मिट्टी या 50 किलोग्राम कम्पोस्ट खाद में 5 किलोग्राम जैव उर्वरक को अच्छी तरह मिलायें। इस मिश्रण को एक हैक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के समय या बुआई से 24 घंटे पहले समान रूप से छिड़कें। इसे बुआई के समय कूड़ों में भी डाल सकते हैं।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

विभिन्न जैव उर्वरक, मात्रा एवं संस्तुत प्रयोग विधि

जैव उर्वरक	उपयुक्त फसलें	संस्तुत प्रयोग विधि	आवश्यक मात्रा
राइजोबियम	सभी दलहनी फसलों के लिये	बीजोपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज
एजोटोबैक्टर	दलहनी फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों के लिये	बीजोपचार, जड़ उपचार, व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
एसिटोबैक्टर	केवल गन्ने के लिये	बीजोपचार, व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
एजोस्पिरिलम	दलहनी फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों के लिये, गन्ने के लिये विशेष उपयोगी	बीजोपचार, जड़ उपचार,व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
फास्फोबैक्टीरिया	सभी फसलों के लिये	बीजोपचार, जड़ उपचार व मृदा उपचार	200 ग्राम प्रति 10-15 किग्रा बीज या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर
माइकोराइजा	सभी फसलों के लिये	मृदा उपचार	5-7 किग्रा प्रति हेक्टेयर
पोटैशियम घोलक जीवाणु	सभी फसलों के लिये	मृदा उपचार	2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर
जिंक घोलक जीवाणु	सभी फसलों के लिये व मृदा उपचार	बीजोपचार, जड़ उपचार	100 मिली प्रति 10-15 किग्रा बीज या 1-2 किग्रा प्रति हेक्टेयर
नील हरित शैवाल	मृदा उपचार धान फसल के लिये		10-12 किग्रा प्रति हेक्टेयर

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला - सभी फसलों# के लिए हर किसान के बजट के अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिचाई व्यवस्था के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।

(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेव्हर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज

जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास २
साईज - १६, २० मिमी

जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (०.33, ०.38 मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन ड्रिप® प्रति बूँद, फसल भरपूर!®
जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि. छोटे छोटे कदम, आसमान छूने का दम!®

दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाईट: www.jains.com

ड्रिपलाईन व फिटींग्ज | ड्रिपर्स | रेनपोर्ट स्प्रिंकलर | स्प्रे हेड व जेटस् | वॉल्व | फिल्टर्स | फिल्ट्रेशन संसाधन | फर्टिगेशन संसाधन | पीव्हीसी पाईप व फिटींग्ज | एचडीपीई पाईप्स व फिटींग्ज | क्विक कनेक्ट पाइप | ऑटोमेशन व कन्ट्रोलर्स

सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

फलों में पोषक तत्वों का मूल्यांकन

● उपेन्द्र यादव ● हंस राज वर्मा
शोध छात्र, फल विज्ञान विभाग
● विवेक यादव
एमएससी छात्र, फल विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उप्र)
upendray123123@gmail.com

फलों के पौधों के लिए अपनाई जाने वाली प्रबंधन प्रणाली, विशेषकर पोषक तत्वों के संबंध में, खेत की फसलों के लिए अपनाई गई प्रबंधन प्रणाली से काफी भिन्न होती है। पेड़ के आकार के आधार पर प्रबंधन प्रणाली में बदलाव रोपण के 3-4 साल बाद शुरू किया जा सकता है। फूल आने और फल लगने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, साथ ही पेड़ों को बढ़ने और अगले वर्षों में उच्च पैदावार देने के लिए पर्याप्त शक्ति बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। लंबे समय तक पेड़ों की उत्पादकता बनाए रखने और पौधों की उत्पादन क्षमता की स्थिरता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्धता पर आधारित होना चाहिए। पौधों में पोषक तत्वों का किफायती ढंग से सही समय पर सही मात्रा में उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि पौधों द्वारा पोषक तत्वों को कम से कम नुकसान के साथ कुशलतापूर्वक ग्रहण किया जा सके। फलों के पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता के आकलन का उद्देश्य पौधों में खनिज पोषक तत्वों के स्तर को वांछित सीमा में बनाए रखना है ताकि पेड़ों की वृद्धि, विकास और वांछित फलन प्राप्त हो सके।

मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक

- वनस्पति आवरण का प्रकार; जैसे दलहनी फसलों के साथ नाइट्रोजन अधिक होता है
- खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग
- मृदा संशोधन का अनुप्रयोग
- मिट्टी की विरासत स्थिति

पत्ती में पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक

- उर्वरक का प्रयोग
- वनस्पति आवरण का प्रकार; जैसे फलियां कवर के साथ नाइट्रोजन अधिक हो सकता है।
- पेड़ में निहित कारक; आनुवंशिक संरचना, पौधे की उम्र, नमूना लेने का समय; वार्षिक (मौसमी) भिन्नता, पत्तियों की आयु, पत्तियों की स्थिति।

पत्तियों के नमूने

फलों के पेड़ों की पोषण संबंधी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए पत्ती विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। पत्ती में पोषक तत्वों का उचित विश्लेषण पत्तियों के ऊतकों का विश्लेषण करके प्राप्त की जा सकता है। इसके बाद पोषक तत्वों की पूर्ति उनकी कमी इष्टतम मानदंडों के अनुसार पौधो को प्रदान की जाती है।

फलों की फसलों के लिए पौधों के ऊतकों के नमूने के दिशा निर्देश

फल	सूचकांक ऊतक	वृद्धि चरण
अंगूर	आधार से 5वाँ डंठल	उपज पूर्वानुमान के लिए कली विभेदन चरण, डंठल
केला	शीर्ष से तीसरी खुली पत्ती का डंठल	कली विभेदन चरण
शरीफा	शीर्ष से पाँचवाँ पत्ता	नई वृद्धि के 2 महीने बाद
अंजीर	पूरी तरह से विस्तारित पत्तियां, मध्य शूट वर्तमान विकास	जुलाई-अगस्त
अमरूद	हाल ही में पकी पत्तियों का तीसरा जोड़ा	खिलने की अवस्था
नींबू	नई फ्लश से 3 से 5 महीने पुरानी पत्ती, अंकुर का पहला पत्ता	जून
आम	पत्तियां डंठल	अंकुर के बीच से 4 से 7 महीने पुरानी पत्तियाँ
अनार	शीर्ष से आठवीं पत्ती	कली विभेदन, फरवरी की फसल के लिए अप्रैल में और जून की फसल के लिए अगस्त में
पपीता	शीर्ष से छठा डंठल	रोपण के 6 महीने बाद
फालसा	शीर्ष से चौथा पत्ता	छंटाई के एक महीने बाद
बेर	द्वितीयक या तृतीयक प्ररोह के शीर्ष से 16वीं पत्ती	छंटाई के दो महीने बाद
चीकू	शीर्ष से 10वीं पत्ती	सितम्बर

बागवानी फसलों के लिए इष्टतम मानदंड

पोषक तत्व	अंगूर (थॉम्पसन बीजरहित)	आम (तोतापुरी)	कागज़ी नींबू	अनार	केला (रोबूस्टा)
नाइट्रोजन (%)	0.87-1.61	0.84-1.53	1.53-2.10	0.91-1.66	1.67-3.43
फास्फोरस (%)	0.29-0.65	0.64-0.15	0.10-0.15	0.12-0.18	0.12-0.21
पोटेशियम (%)	2.0-3.0	0.52-1.10	0.96-1.66	0.61-1.59	2.28-4.14
कैल्शियम (%)	0.98-1.36	1.97-3.20	3.05-3.43	0.77-2.00	0.48-1.70
मैग्नीशियम (%)	0.63-1.10	0.40-0.65	0.40-0.60	0.16-0.42	0.33-0.58
सल्फर (%)	0.09-0.13	0.15-0.22	0.25-0.29	0.16-0.26	0.03-0.18
आयरन (पीपीएम)	54-80	48-86	117-194	71-214	53-196
मैंगनीज (पीपीएम)	42-209	57-174	21-63	29-89	112-417
जिंक (पीपीएम)	30-88	25-33	25-50	14-72	8-38
कॉपर (पीपीएम)	5-10	3.1-8.0	8.7-14.8	29-72	10-32

मिट्टी की सेहत बचाएं, खेत की उपज बढ़ाएं

● श्रीयांशु राठौर, shriyanshurathore2002@gmail.com

मिट्टी बचेगी तभी खेती टिकेगी

किसानों भाइयों और बहनों,

हमारी खेती की असली ताकत मिट्टी है। मिट्टी नहीं तो अनाज नहीं। लेकिन आज लगातार ज्यादा जुताई, रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई और बारिश का बहाव हमारी मिट्टी को खराब कर रहा है।

जिस जमीन से हम रोज़ी-रोटी कमाते हैं, वही अगर कमजोर हो जाए, तो हमारी खेती भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आज सबसे जरूरी है - मृदा संरक्षण यानी मिट्टी की रक्षा।

मिट्टी बिगाड़ने वाले काम

- बार-बार खेत को जोतना
- सिर्फ एक ही फसल बार-बार लगाना
- जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद डालना
- पेड़-पौधे काट देना
- बिना योजना के सिंचाई करना

मिट्टी बचाने के आसान उपाय

फसल चक्र अपनाएं: गेहूं के बाद दलहनी फसलें (जैसे मूंग, उड़द) लगाएं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है।

जैविक खाद डालें: गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट से मिट्टी की ताकत बढ़ती है।

पौधे लगाएं (वनरोपण): खेत की मेड़ों पर पेड़ और झाड़ियाँ लगाएं। इससे मिट्टी बहती नहीं है।

सीढ़ीनुमा खेती : पहाड़ी या ढलान वाले इलाकों में यह तरीका बहुत कारगर है।

कंटूर नाली बनाएं: पानी को सीधे नीचे बहने से रोकें। इससे मिट्टी नहीं बहती और जल भी बचता है।

मिट्टी की जांच कराएं: 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के तहत सरकार मुफ्त में मिट्टी की जांच करवाती है।

सरकार से मदद कैसे लें?

कृषि विभाग से संपर्क करें - अपने जिले के कृषि अधिकारी से सलाह लें।

कृषि विज्ञान केंद्र - हर जिले में मौजूद हैं। वहां से मृदा संरक्षण पर प्रशिक्षण मिल सकता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - इस योजना के तहत हर किसान को बताया जाता है कि उसकी जमीन में कौन-कौन से पोषक तत्व कम हैं।

लेखक की बात

मिट्टी हमारी माँ है। माँ को बीमार नहीं होने देना है। अगर आज से हम मृदा संरक्षण शुरू करें, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ ज़मीन मिलेगी।

तो आइए, हम सब मिलकर मिट्टी की रक्षा करें और खेती को समृद्ध बनाएं।

पोल्ट्री में कूड़ा प्रबंधन

कूड़ा प्रबंधन टिकाऊ पोल्ट्री उत्पादन की आधारशिला है, जिसका सीधा प्रभाव पक्षियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और सामुदायिक स्वीकृति पर पड़ता है। पोल्ट्री उत्पादकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से, मक्खियों का प्रकोप और लगातार आने वाली दुर्गंध को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। ये समस्याएँ न केवल फार्म की स्वच्छता को प्रभावित करती हैं, बल्कि रोग संचरण, नियामक जाँच और पड़ोसी समुदायों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का जोखिम भी पैदा करती हैं। हालाँकि भौतिक और रासायनिक हस्तक्षेपों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन उनकी सीमाएँ तेज़ी से स्पष्ट होती जा रही हैं, जिससे अधिक समग्र समाधानों की आवश्यकता बढ़ रही है।

समस्या का पैमाना

लेयर फ़ार्म में, खाद लंबे समय तक जमा होती रहती है। उच्च कार्बनिक तत्व, नमी और गर्मी के साथ मिलकर, सूक्ष्मजीवों के अपघटन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। इस अपघटन से अमोनिया और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) निकलते हैं, जिससे विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है। साथ ही, खाद मक्खियों, विशेष रूप से घरेलू मक्खी (मस्का डोमेस्टिका) के लिए प्रजनन स्थल बन जाती है, जो नम कूड़े में पनपती है।

ये मक्खियाँ केवल एक उपद्रव ही नहीं हैं- ये साल्मोनेला, ई. कोलाई और कैम्पिलोबैक्टर जैसे रोगजनकों के लिए यांत्रिक वाहक का काम करती हैं। इस बीच, गंध उत्सर्जन न केवल फ़ार्म की हवा की गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि आस-पास के समुदायों की शिकायतों को भी बढ़ाता है, जो अक्सर नियामक चुनौतियों का कारण बनता है।

हस्तक्षेप और उनकी सीमाएँ

उत्पादक लंबे समय से भौतिक हस्तक्षेपों पर निर्भर रहे हैं, जैसे-

- प्रजनन सामग्री को कम करने के लिए बार-बार खाद हटाना।
- गंध को दूर करने और कूड़े को सूखा रखने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम।
- यांत्रिक टर्नर का उपयोग करके कूड़े को सुखाना और वातन करना।
- वयस्क मक्खियों की आबादी को कम करने के लिए जाल।

हालाँकि ये उपाय अस्थायी राहत प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में ये अक्सर विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए-

- बार-बार खाद हटाना श्रमसाध्य और महंगा है, खासकर बड़े पैमाने पर संचालन में।
- वेंटिलेशन गंध को दूर करता है लेकिन इसके स्रोत को खत्म नहीं करता है।
- यांत्रिक सुखाने का काम असंगत है, खासकर आर्द्र या बरसात के मौसम में।
- जाल और जाल वयस्कों की संख्या को कम करते हैं लेकिन मूल कारण कूड़े में मक्खियों का प्रजनन को संबोधित नहीं करते हैं।

रासायनिक हस्तक्षेप और उनकी कमियाँ

कीटनाशक, लार्वानाशक, कीटाणुनाशक और कूड़े में सुधार जैसे रासायनिक हस्तक्षेप, पोल्ट्री अपशिष्ट प्रबंधन में आम उपकरण हैं। हालाँकि, उनकी सीमाएँ तेजी से पहचानी जा रही हैं-

- मक्खियों की आबादी में कीटनाशक प्रतिरोध तेज़ी से विकसित होता है, जिससे समय के साथ उनकी प्रभावशीलता कम होती जाती है।
- रासायनिक अवशेष कूड़े को दूषित कर सकते हैं, जिससे फसल के उपयोग या खाद बनाने में चिंताएँ पैदा हो सकती हैं।
- फिटकरी या चूने जैसे अमोनिया-बाध्यकारी रसायन अस्थायी रूप से गंध को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बार-बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है।
- रसायनों पर अत्यधिक निर्भरता कूड़े के सूक्ष्मजीवी संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे कभी-कभी गंध की उत्पत्ति और भी बदतर हो जाती है।

इसके अलावा, रासायनिक अवशेषों और स्थायित्व से जुड़ी पर्यावरणीय और उपभोक्ता चिंताएँ, खेतों को इन तरीकों पर पूरी तरह निर्भर रहने से दूर जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

आवर्ती मक्खी चक्र : लार्वा नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है

मक्खियाँ अपने तेज़ और आवर्ती जीवन चक्र के कारण लगातार जीवित रहती हैं। एक घरेलू मक्खी नम खाद पर सैकड़ों अंडे दे सकती है, जो 24 घंटे के भीतर लार्वा (मैगॉट्स) में बदल जाते हैं। ये लार्वा अनुकूल परिस्थितियों में 10 दिनों से भी कम समय में प्यूपा बन जाते हैं और वयस्क बन जाते हैं। जब तक कूड़ा नमी, गर्मी और पोषक तत्व प्रदान करता रहता है, यह चक्र अनवरत चलता रहता है।

केवल वयस्क मक्खियों को लक्षित करना एक अल्पकालिक रणनीति है। यदि वयस्कों को भी नष्ट कर दिया जाए, तो कुछ ही दिनों में नई पीढ़ियाँ उभर आती हैं, जिससे संक्रमण फिर से फैल जाता है। मक्खियों को नियंत्रित करने का एकमात्र स्थायी तरीका लार्वा अवस्था में ही इस चक्र को तोड़ना है। कूड़े को सुखाने, पोषक तत्वों को स्थिर करने, या लार्वा के विकास को सीधे दबाने वाले हस्तक्षेप मक्खियों की आबादी को उनके स्रोत पर ही नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। लार्वा पर ध्यान केंद्रित करके, उत्पादक जाल और कीटनाशकों से वयस्क मक्खियों का लगातार पीछा करने के बजाय भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोक सकते हैं।

वर्तमान दृष्टिकोण अपर्याप्त क्यों हैं?

मक्खियों और दुर्गंध की समस्याओं का बने रहना एक महत्वपूर्ण बात को उजागर करता है- भौतिक और रासायनिक हस्तक्षेप मुख्यतः लक्षणों को संबोधित करते हैं, कारणों को नहीं। मक्खियाँ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि गोबर पोषक तत्वों से भरपूर और उनके जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नम रहता है। दुर्गंध इसलिए बनी रहती है क्योंकि यूरिक एसिड और प्रोटीन का सूक्ष्मजीवी विघटन अनियंत्रित रूप से जारी रहता है। जब तक कूड़ा जैविक रूप से अस्थिर रहेगा, बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद ये समस्याएँ फिर से उभरती रहेंगी।

सतत प्रबंधन की ओर बढ़ना

वर्तमान रणनीतियों की सीमाएँ एकीकृत, जीव-केंद्रित दृष्टिकोणों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं जो खाद को स्रोत पर ही स्थिर कर सकें। कूड़े में सूक्ष्मजीवी गतिविधि और पोषक तत्वों की गतिशीलता को संशोधित करके, यह संभव हो जाता है-

- अमोनिया उत्सर्जन और गंध निर्माण को कम करना।
- मक्खी प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सीमित करना।
- कूड़े के मूल्य को एक सुरक्षित, पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरक के रूप में बेहतर बनाना।

ऐसे दृष्टिकोण न केवल दीर्घकालिक परिणाम प्रदान करते हैं, बल्कि पोल्ट्री उद्योग के स्थायित्व, जैव सुरक्षा और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं की ओर बढ़ने के प्रयासों के अनुरूप भी हैं।

मृदा स्वास्थ्य एवं टिकाऊ खेती...

(पृष्ठ 5 का शेष)

जैव उर्वरकों के उपयोग में सावधानियां

● नाइट्रोजन जैव उर्वरकों के साथ फास्फोबैक्टीरिया का प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है। प्रत्येक दलहनी फसल के लिये अलग राइजोबियम कल्चर तैयार किये जाते हैं। अतः दलहनी फसल के अनुरूप ही राइजोबियम कल्चर क्रय कर प्रयोग करें।

● जैव उर्वरकों को धूप में कभी न रखें, यदि इसे कुछ दिनों के लिये रखना हो तो मिट्टी के घड़े का प्रयोग बहुत अच्छा है। ● फसल विशेष के अनुसार ही जैव उर्वरक का चुनाव करें। ● रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाईयों से जैव उर्वरकों को दूर रखें तथा इनका एक साथ प्रयोग भी न करें। ● जब बीज को फफूंदनाशक दवा से भी उपचारित करना हो तो पहले फफूंदनाशक से और फिर जैव उर्वरक से उपचारित करें। ● जैव उर्वरकों की अच्छी कार्यप्रणाली के लिये 20-35 सेण्टीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है। परिवहन के दौरान इन्हें धूप से बचायें साथ ही पर्याप्त नमी होने पर ही खेत में उपयोग करें। ● जैव उर्वरकों का स्वजीवन 6 माह का होता है अतः प्रभाव समाप्ति अवधि के पूर्व ही फसल अनुसार उपयोग करें। ● अम्लीय भूमियों में प्रयोग के लिये उपचारित बीजों पर चूना, डोलोमाइट अथवा सुपर फास्फेट का लेप चढ़ा दें। क्षारीय भूमि में बीजों पर जिप्सम की पर्त चढ़कर बोनी करें।

पोटैशियम प्रदायी जैव उर्वरक (केएसबी)

पोटैशियम प्रदायी जैव उर्वरक भूमि में उपस्थित अघुलनशील पोटैशियम को घुलनशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः पोटैशियम की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे- म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी), सल्फेट ऑफ पोटाश (एसओपी) का 50 से 60 प्रतिशत भाग ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो पाता है। पोटैशियम प्रदायी जैव उर्वरक, भूमि में उपस्थित 40 से 50 प्रतिशत अघुलनशील पोटैशियम को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास अच्छा होने से उत्पादन में 20-25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है।

विभिन्न फसलों हेतु उपयोगी राइजोबियम प्रजातियां

राइजोबियम की प्रजाति	फसल
राइजोबियम लेग्युमिनोसेरम	मटर, मसूर एवं खेसारी
राइजोबियम फेसियोलाई	राजमा
राइजोबियम ट्राईफोलाई	बरसीम
राइजोबियम ल्यूपिनी ल्यूपिन	वार्षिक एवं बहुवार्षिक
राइजोबियम मिलिलोटाई	लूर्सन, मेथी एवं स्वीट क्लोवर
राइजोबियम स्पेसीज	लोबिया, चना, मोथ, कुल्थी

जिंक प्रदायी जैव उर्वरक (जेडएसबी)

जिंक प्रदायी जैव उर्वरक भूमि में उपस्थित अघुलनशील जिंक को घुलनशील व गतिशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। सामान्यतः जिंक की पूर्ति हेतु प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों जैसे- जिंक सल्फेट का 5 से 10 प्रतिशत भाग ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो पाता है। जिंक प्रदायी जैव उर्वरक, भूमि में उपस्थित अघुलनशील जिंक को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधों की वृद्धि व विकास अच्छा होने से उत्पादन में 10-15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है।

राइजोबियम प्रजातियों द्वारा दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण की मात्रा

दलहनी फसलें	नत्रजन स्थिरीकरण (किग्रा/हे.)
अरहर	70-200
ढेंचा	100-120
उड़द-मूंग	70-90
लोबिया	80-85
सोयाबीन	65-120
चना	80-100
मटर	52-77
मसूर	90-100

जैव उर्वरकों के प्रयोग से लाभ

● ये अन्य रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं जिससे फसल उत्पादन की लागत घटती है। ● जैव उर्वरकों के प्रयोग से नाईट्रोजन, घुलनशील फास्फोरस, पोटैशियम व जिंक आदि की फसल के लिये उपलब्धता बढ़ती है। ● इससे रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो जाता है जिससे भूमि की मृदा संरचना अच्छी बनी रहती है। ● जैव उर्वरक से पौधों में वृद्धिकारक हारमोन्स उत्पन्न होते हैं जिनसे उनकी बढ़वार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ● जैव उर्वरक से फसल में मृदाजन्य रोग नहीं होते हैं। ● जैविक खाद से खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

खाद्य सुरक्षा और सहकारिताओं की भूमिका

● डॉ. आर. एस. सेंगर ● गरिमा शर्मा
● डॉ. शालनी गुप्ता ● डॉ. निधि सिंह
पादप जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग
सरदार वल्लभभाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ

आज भी भंडारण की कमी, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और कमजोर वितरण प्रणाली बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने 2023 में सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना में प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) अहम भूमिका निभा रही हैं, जो किसानों से अनाज खरीदकर सुरक्षित भंडारण और आगे वितरण का काम करती हैं। सहकारिताएँ अब सिर्फ़ एक संस्था नहीं, बल्कि बहुआयामी और बहुउद्देश्यीय संगठन बन चुकी हैं। ये किसानों से उचित दाम पर अनाज खरीदकर उपभोक्ताओं को भी वाजिब दाम पर उपलब्ध कराती हैं। कई जगहों पर अनाज बैंक और सहकारी दुकानें चल रही हैं, जो खाद्य सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करती हैं।

अमूल जैसे सफल सहकारी मॉडल और महाराष्ट्र के अनाज बैंक इस बात के उदाहरण हैं कि सामूहिक शक्ति से न सिर्फ़ भंडारण की समस्या हल हो सकती है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को भी मज़बूती मिलती है। सहकारिता मंत्रालय भी अब विकेन्द्रीकृत भंडारण योजना ला रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर भंडारण बढ़ेगा और किसानों को बाज़ार तक बेहतर पहुँच मिलेगी। अगर ग्रेडिंग, छँटाई और सही संचालन पर ज़ोर दिया जाए, तो खाद्य सुरक्षा का सपना और मज़बूत हो सकता है। सहकारी समितियाँ इस दिशा में टिकाऊ और न्यायपूर्ण विकास का रास्ता दिखाती हैं।

> खाद्य सुरक्षा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक है। यह सिर्फ़ बाज़ार में अनाज की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आम लोग इन्हें आसानी से खरीद और इस्तेमाल कर पाएँ।

भारत की खाद्य सुरक्षा और भंडारण चुनौती

भारत के पास दुनिया की कुल खेती योग्य भूमि का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा (16 करोड़ हेक्टेयर) है, जबकि यहाँ दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी (140 करोड़ लोग) रहती है। यानी हमें सीमित ज़मीन पर ज्यादा लोगों की भूख मिटानी है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 2021 के आँकड़ों के अनुसार, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है, लेकिन देश में सुरक्षित भंडारण की क्षमता केवल 145 MMT ही है। इसका मतलब है कि हमारे पास करीब 166 MMT की भारी कमी है। यही नहीं, भारत में भंडारण अवसंरचना में लगभग 47 प्रतिशत की कमी है। नतीजा यह होता है कि कटाई के बाद अनाज का बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है और वितरण प्रणाली भी कमजोर पड़ती है।

इन चुनौतियों को देखते हुए, भारत सरकार ने 2023 में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इस योजना को ज़मीन पर उतारने में प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) बड़ी भूमिका निभाएँगी।

आज PACS सिर्फ़ किसानों को ऋण देने या बीज-खाद उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अब अनाज की ख़रीद, भंडारण और गाँवों में ज़रूरी सेवाएँ देने जैसे कामों में भी सक्रिय हो रही हैं। अगर इन्हें सही तरीके से मज़बूत किया जाए, तो ये न सिर्फ़ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बन सकती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह योजना सिर्फ़ एक परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है।

भारत में सहकारिता: किसानों की ताकत और ग्रामीण विकास का साधन

भारत में 1.1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) हैं, जिनमें 13 करोड़ किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। ये सहकारी संस्थाएँ छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने, बाजार तक पहुँच बनाने और सुरक्षित भंडारण जैसी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

सहकारिता के कई सफल उदाहरण देश भर में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 94 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सहकारिताओं द्वारा किया जाता है। मदर डेयरी किसानों से दूध और सब्जियाँ खरीदकर तय कीमत पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाती है। अमूल ने भारत में दुग्ध उत्पादन और किसान लाभ को बढ़ावा दिया है। महाराष्ट्र में अकादमी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ने जनजातीय और ग्रामीण समुदायों के लिए अनाज बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ किसान अतिरिक्त अनाज जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऋण के रूप में ले सकते हैं।

साथ ही, NAFED आवश्यक वस्तुओं जैसे दाल और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखता है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि सहकारी संस्थाएँ केंद्रीकृत खरीद और भंडारण के माध्यम से ग्रामीण और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

हालाँकि, PACS स्तर पर संचालन और प्रबंधन में चुनौतियाँ हैं। कई भंडारण संरचनाएँ पूरी तरह से प्रबंधित नहीं हो पाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिताओं को आर्थिक विकास का प्रभावी साधन माना है और इनके सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करने पर जोर दिया है। इसी दृष्टि से सहकारिता मंत्रालय ने PACS के विविधीकरण और क्षमता निर्माण के लिए दूरदर्शी योजना बनाई है। सहकारी समितियाँ सिर्फ़ किसानों के लिए वित्तीय मदद नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और सतत आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार हैं।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनाज भंडारण योजना

- किसान पैक्स में बने गोदाम में अपनी उपज रख सकेंगे।
- वे फसल के अगले चक्र के लिए ब्रिज फाइनेंस भी प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान अपनी पसंद के समय पर उपज बेच सकते हैं।
- वे अपनी पूरी फसल एमएसपी पर पैक्स को बेचने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
- किसान पंचायत/गांव स्तर पर भी विभिन्न कृषि इनपुट और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

'पैक्स' और खाद्य सुरक्षा

'पैक्स' (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पीएमएफएमई और कृषि अवसंरचना निधि जैसी योजनाएँ संचालित की गई हैं। 31 मई 2023 को भारत सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर अगले पाँच वर्षों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाने का लक्ष्य है। इस योजना में देशभर के 67,000 सक्रिय पैक्स को शामिल किया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपर्याप्त भंडारण क्षमता को दूर करना है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान, गुणवत्ता गिरावट और उच्च परिवहन लागत जैसी समस्याओं को कम करने के लिए विकेन्द्रीकृत और मजबूत भंडारण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। किसान स्थानीय स्तर पर अपनी उपज सुरक्षित रख सकेंगे और पैक्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे खरीद में मदद करेंगे।

इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि पैक्स बहु-कार्यात्मक व्यावसायिक इकाइयों में बदलेंगे। 2025 तक 11 राज्यों में 11 पैक्स में गोदाम बन चुके हैं और 500 पैक्स में निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है। यह योजना भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के समन्वय से तेजी से लागू हो रही है।

योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोदाम निर्माण

क्र.	राज्य	जिला	PACS* का नाम	गोदाम की क्षमता (MT)
1.	महाराष्ट्र	अमरावती	नेरिपांगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	3,000
2.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लि., कोटवा पांडे	1,500
3.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, परसवाड़ा	500
4.	गुजरात	अहमदाबाद	चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लि.	750
5.	तमिलनाडु	थेनी	सिलामरथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति	1,000
6.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	घुमदवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	250
7.	तेलंगाना	करीमनगर	प्राथमिक कृषि ऋण समिति लि., गंभीरापेट	500
8.	कर्नाटक	बीदर	प्राथमिक कृषि सहकारी महासंघ लि., एकांबा	1,000
9.	त्रिपुरा	गोमती	खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति लि.	250
10.	असम	कामरूप	2 नं. पब बोंगशर जी.पी.एस.एस. लि., बहुद्देशीय किसान सेवा समिति	500
11.	उत्तराखंड	देहरादून	सहकारी समिति लि., सहसपुर	500
			कुल	9,750

भारत में खाद्य भंडारण: चुनौतियाँ और सहकारी समाधान

अध्ययन बताते हैं कि भारत में खाद्य भंडारण संरचनाएँ अपर्याप्त और कमजोर हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है। खराब वेयरहाउसिंग की वजह से किसानों को अक्सर अपने अनाज को जल्दी और कम कीमत में बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। अनुमान के अनुसार, खराब भंडारण के कारण प्रतिवर्ष कुल खाद्यान्न का 10-15 प्रतिशत नष्ट हो जाता है, जिसका वित्तीय असर लगभग 90,000 करोड़ रुपये है (गुलाटी एट अल., 2024)। खाद्य भंडारण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए सहकारी मॉडल को जोखिम कम करने और नुकसान घटाने के लिए प्रभावी उपाय के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं-भंडारण क्षमता की कमी, अनाज की बर्बादी, गुणवत्ता में गिरावट, उच्च भंडारण लागत और लक्षित वितरण में कठिनाई।

सहकारी समितियाँ इन समस्याओं का समाधान पेश कर सकती हैं। ये किसानों से अनाज सुरक्षित रूप से खरीद सकती हैं, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ प्रदान कर सकती हैं और नुकसान कम करके खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं।

कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक, जैविक खेती को करें प्रोत्साहित : डॉ. मोहन यादव

भोपाल (कृषक जगत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि उपज पर आधारित राज्य है, इसलिए सरकार का प्रमुख लक्ष्य प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना और उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर कृषि उद्यमिता, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गतदिनों कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025 के पहले सत्र 'कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स' को संबोधित कर रहे थे।

प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मिले बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को जैविक दिशा में ले जाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे पार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि हर जिले के कलेक्टर कम से कम 100 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करें और उनके लाभों का रिकॉर्ड रखें।

डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर हाट बाजारों और साप्ताहिक मार्केट्स में जैविक उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को सीधा बाजार मिल सके।

उद्यानिकी और मिलेट्स पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केला, संतरा, टमाटर जैसी उद्यानिकी फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं। इनका स्थानीय प्रसंस्करण और बाजार तक मार्केटिंग व्यवस्था मज़बूत की जाएगी। उन्होंने कहा कि 'श्री अन्न' की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि राज्य आत्मनिर्भर और पोषण समृद्ध बन सके।

उन्होंने गुना जिले में गुलाब की खेती के नवाचार की सराहना की और कहा कि धार्मिक शहरों में भी गुलाब उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।

मुख्य बिंदु

- किसानों को नकद फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा
- रबी 2025-26 के लिए उर्वरक वितरण पर चर्चा
- कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन नीलामी दरों की निगरानी के निर्देश
- जिलों में कृषक संगोष्ठियों के आयोजन पर बल

भावांतर भुगतान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार

डॉ. यादव ने कहा कि भावांतर योजना का प्रचार-प्रसार तेज़ किया जाए ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं।

पराली और नरवाई जलाने पर सख्त नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। किसानों को वैकल्पिक समाधान जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर मशीनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।

भावांतर योजना में अब तक 1.15 लाख किसानों का पंजीयन

कृषि सचिव श्री बरवड़े ने ली बैठक

भोपाल (कृषक जगत)। प्रदेश के कृषि सचिव श्री निशांत बरवड़े ने वल्लभ भवन स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से प्रदेश की सभी 259 मंडी समितियों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन और सोयाबीन खरीदी 2025 की तैयारियों की समीक्षा की गई।

200 मंडियों और 80 उपमंडियों में होगी खरीदी

श्री बरवड़े ने बताया कि प्रदेश की लगभग 200 मंडियों में सोयाबीन की आवक होती है। इस वर्ष 80 से अधिक उपमंडियों में भी भावांतर भुगतान योजना लागू की जाएगी। इन मंडियों में ई-मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अब तक 1.15 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। 24 अक्टूबर से मंडियों में सोयाबीन खरीदी प्रारंभ होगी।

मंडियों में किसानों की सुविधा सर्वोपरि

कृषि सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य दिवस में पहली नीलामी के दौरान मंडी सचिव और भारसाधक अधिकारी स्थल पर उपस्थित रहें तथा नीलामी की प्रक्रिया की निगरानी करें।

कृषि विपणन बोर्ड ने साझा की कार्ययोजना

बैठक के दूसरे चरण में मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मंडी सचिवों से वन-टू-वन चर्चा की। इस दौरान अपर प्रबंध संचालक श्री अनुराग सक्सेना ने योजना की तकनीकी जानकारी पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से साझा की।

एमएसपी पर धान, ज्वार, बाजरा के लिए 4 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए अभी तक 4 लाख 68 हजार 946 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष 7 लाख 84 हजार 845 किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि समय पर पंजीयन करा लें जिससे उपार्जन में कोई समस्या नहीं हो। प्रदेश में 1255 पंजीयन केन्द्र बनाये गये हैं।

राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान का 14वाँ स्थापना दिवस

रायपुर। आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (NIBSM), रायपुर का 14वाँ स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. मंगला राय, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, आईसीएआर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. राय ने अपने महानिदेशक, आईसीएआर के कार्यकाल के दौरान इस संस्थान की परिकल्पना एवं स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कार्यक्रम में डॉ. टी. पी. राजेन्द्रन, पूर्व सहायक महानिदेशक (पादप संरक्षण), डॉ. पियूष पाण्डेय, कुलपति, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ तथा डॉ. जे. कुमार, पूर्व संयुक्त निदेशक, आईसीएआर-एनआईबीएसएम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम में डॉ. मंगला राय ने वन हेल्थ की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा जैविक और अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन के बीच समन्वय की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी को किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु नवाचारी एवं टिकाऊ उपकरण विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। डॉ. पी. के. राय, निदेशक, आईसीएआर-एनआईबीएसएम ने संस्थान की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया तथा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने हेतु उच्च शिक्षा एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर दो प्रगतिशील किसानों को सतत कृषि पद्धतियों में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों में संस्थान के श्रेष्ठ कर्मचारियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर एक संकलन, तकनीकी पुस्तिकाएँ एवं नीति पत्र भी अतिथियों द्वारा जारी किए गए।

अतिथियों का स्वागत एवं उद्बोधन तथा कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक, आईसीएआर-एनआईबीएसएम द्वारा किया गया।

प्रदेश में 138 लाख... (प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य में 50 लाख टन उर्वरक की मांग

इस वर्ष सरसों का रकबा गत वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है। वहीं रबी की नकदी फसल गन्ने की बुवाई 1.32 लाख में होगी। खाद्यान्न फसलों के तहत जौ की बोनी इस वर्ष 34 हजार हेक्टेयर में होगी, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। गत वर्ष 24 हजार हेक्टेयर में जौ की बोनी हुई थी।

जानकारी के मुताबिक रबी 2025-26 के लिए कुल 49.50 लाख मीट्रिक टन राज्य द्वारा उर्वरक की मांग गई है। इसके तहत प्रमुख उर्वरकों में सीजन के लिए यूरिया की 23 लाख मीट्रिक टन, एसएसपी 6.50 लाख मीट्रिक टन एवं एमओपी की 1 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 7.50 लाख मीट्रिक टन एवं काम्पलेक्स 11.50 लाख मीट्रिक टन की मांग की गई है।

वहीं राज्य में संभाग स्तर पर बुवाई का लक्ष्य देखें तो सबसे अधिक जबलपुर संभाग में 21 लाख 51 हजार हेक्टेयर में तथा सबसे कम शहडोल संभाग में 3 लाख 14 हजार हेक्टेयर में रबी बोनी की जाएगी।

रबी बुवाई के लिए राज्य के टॉप 10 संभाग
(लाख हे. में)

संभाग	बुवाई लक्ष्य
जबलपुर	21.51
उज्जैन	20.39
भोपाल	19.22
सागर	18.83
इंदौर	15.44
ग्वालियर	14.70
रीवा	9.53
नर्मदापुरम्	8.22
मुरैना	7.83
शहडोल	3.14

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

उर्वरक वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में जबलपुर जिला भी शामिल

जबलपुर (कृषक जगत)। किसानों को उर्वरक वितरण की एक अक्टूबर से लागू की गई नई व्यवस्था 'किसान पंजीयन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली' के पायलट प्रोजेक्ट में जबलपुर जिले को भी शामिल किया गया है। किसानों को सुगमता से समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कृषि विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की जा रही इस व्यवस्था के पायलट प्रोजेक्ट में जबलपुर जिले के अलावा शाजापुर और विदिशा जिले को भी शामिल किया गया है।

उप संचालक कृषि डॉ. एस. के. निगम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उर्वरक वितरण की यह व्यवस्था मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर एवं क्यूआर कोड पर आधारित है तथा ई-उपार्जन पोर्टल पर धान एवं गेहूं के उपार्जन के लिये पंजीयन करने की प्रक्रिया के समान है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में सबसे पहले किसानों को आधार नम्बर का उपयोग कर अपना पंजीयन करना होगा। इसका आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा।

उप संचालक कृषि के मुताबिक वेरिफिकेशन के बाद किसान की जानकारी के साथ भू-अभिलेख की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक का चयन कर लिये जाने के बाद वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता की जानकारी किसानों को प्राप्त होगी। इसके बाद किसान स्लॉट बुकिंग की तरह उर्वरक विक्रेता का चयन कर सकेंगे। विक्रेता का चयन करने पर एक कूपन जनरेट होगा जिस पर क्यूआर कोड भी होगा। प्राप्त कूपन को किसान संबंधित उर्वरक विक्रेता को उपलब्ध करायेगा। उर्वरक विक्रेता क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। इससे किसान को उपलब्धन कराये जाने वाले उर्वरक की जानकारी प्रदर्शित होगी और विक्रेता द्वारा किसान को उर्वरक उपलब्धक कराया जायेगा। इसकी जानकारी तुरंत ही किसान के मोबाइल पर मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। उप संचालक ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत उर्वरक प्राप्त किसानों को किसी भी प्रकार के टोकन की आवश्यकता नहीं होगी तथा डीलर, डबल लॉक केन्द्र या समिति का पहले ही चयन कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा।

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ का शुद्ध लाभ 20 करोड़ 54 लाख

इंदौर (कृषक जगत)। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर का 42वां वार्षिक साधारण सभा का सम्मेलन नगर के गुरू अमरदास हॉल में सम्पन्न हुआ। वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता करते हुए दुग्ध संघ के प्राधिकारी अधिकारी व संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने उद्बोधन देते हुए कहा कि इंदौर दुग्ध संघ लगातार अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2024-25 में 707.34 करोड़ वार्षिक टर्नओवर रहा। जिसमें दुग्ध संघ को 20 करोड़ 54 लाख 27 हजार का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

दुग्ध संघ का कार्य क्षेत्र 9 जिलों में संचालित है। वर्ष 2024-25 में 1523 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के द्वारा 2.93 लाख किलोग्राम प्रति दिन संकलित किया गया। संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने वार्षिक उद्बोधन में वर्ष 2025-26 में संघ द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों के बारे में भी बताया गया। इस वर्ष 550 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन एवं 250 का अकार्यरत दुग्ध समितियों को पुर्नगठित करने के अलावा 240 समितियों को सुदृढ़ीकरण करने और कुल 2323 समितियों से 4.11 लाख किलो ग्राम प्रति दिन दुध संकलन का लक्ष्य रखा गया है।

दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बलवीर शर्मा ने साधारण सभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाते हुए 13 अप्रैल से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इंदौर दुग्ध संघ के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत दुग्ध संघ प्रबंधन एवं संचालन प्रारंभ किया गया है।

वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर प्रबंधकारिणी के डॉ. विल्सन डाबर, संयुक्त संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग इंदौर संभाग इंदौर श्री बीएल मकवाना, संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर संभाग श्रीमती नीलम नीनामा, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, वित्त विभाग इंदौर संभाग श्री दिनेश पटेल, अध्यक्ष प्रबंध समिति सदस्य श्रीमती सपना विष्णु पटेल, प्रबंध समिति सदस्य एवं एमपीसीडीएफ भोपाल के प्रतिनिधि डॉ. शुभांकर नन्दा उपस्थित थे। इसके साथ ही दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती सिंह पटेल, श्री उमराव सिंह मौर्य एवं पूर्व संचालक गण भी उपस्थित रहे।

एक्सपायरी डेट का कीटनाशक मिलने पर दुकान सील

श्योपुर (कृषक जगत)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा कृषि आदान सामग्री विक्रय करने वाली फर्म एवं दुकानों के निरीक्षण किये जाने संबंधी निर्देशों के क्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गत दिनों कीटनाशक का विक्रय करने वाली दुकान मेसर्स- न्यू गणेश ट्रेडिंग कंपनी पाली रोड श्योपुर का औचक निरीक्षण किया गया। दुकान पर एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाएं पाये जाने तथा लाइसेंस में वैध पी.सी. एवं स्टॉक पंजी का संधारण नहीं पाये जाने से दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान कीटनाशक निरीक्षक पदेन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड श्योपुर श्री शरद रघुवंशी, कृषि विस्तार अधिकारी श्री विजय सेन एवं श्री नवल सिंह चौबे उपस्थित रहे।

उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़

नर्मदापुरम (कृषक जगत)। विक्रेता द्वारा बगैर लाइसेंस के एवं अधिक दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. उर्वरक विक्रय करते पाए जाने पर ग्राम रायपुर निवासी मोहन मदनलाल खंडेलवाल के विरूद्ध पुलिस थाना-देहात नर्मदापुरम में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उप संचालक नर्मदापुरम ने बताया कि गत 3 सितम्बर को तहसीलदार नर्मदापुरम (ग्रामीण) दल के साथ मोहन खंडेलवाल, निवासी ग्राम रायपुर की घानावड क्षेत्र में फोरलेन के समीप स्थित दुकान में जांच के दौरान मोहन मदनलाल खंडेलवाल द्वारा कृषक अभयराम को 300 रुपए प्रति बोरी यूरिया बेचते हुए पाया गया, मौके पर दुकान के भीतर डी.ए.पी. 92 बोरी एवं यूरिया 78 बोरियां भंडारित पाई गई तथा दुकानदार मोहन खंडेलवाल के पास खाद-उर्वरक बेचने का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। अवैध कालाबाजारी के तथ्य पाए जाने पर दुकान को तत्काल सीलबंद किया गया।

विस्तृत जांच उपरांत उप संचालक नर्मदापुरम द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत बनाए गए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के नियमों के आधार पर कृत्यकर्ता के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश डॉ. राजीव यादव, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुभाग-नर्मदापुरम को दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी कृषि द्वारा प्रकरण की प्राथमिकी पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम में पंजीबद्ध कराई गई है।

मंडला में 50 हजार का जुर्माना वसूला

मंडला (कृषक जगत)। नैनपुर एसडीएम श्री आशुतोष ठाकुर के मार्गदर्शन में कृषि उपज मण्डी नैनपुर के स्थानीय निरीक्षण/उड़नदस्ता दल द्वारा मण्डी समिति नैनपुर क्षेत्रांतर्गत निरीक्षण के दौरान चिरईडोंगरी (रेल्वे) मार्ग में वाहन क्रमांक एमपी 51जेडडी9313 पर मण्डी नियम के उल्लंघन पर जुर्माने की कार्यवाही की गई।

वाहन में परिवहित अधिसूचित कृषि उपज मक्का वजन 362.00 क्विंटल के मंडी शुल्क/परिवहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा गया। जिस पर वाहन चालक द्वारा मेसर्स सीताराम कुंदनलाल सिवनी द्वारा जारी बिल/कैश मेमो/चालान एवं धर्मकांटा पर्ची प्रस्तुत किया गया। किन्तु गंतव्य स्थल आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) के लिए परिवहन के लिए नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। कृषि उपज मण्डी अधिनियम-1972 की धारा 19(6) का स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना पाया गया।

इस पर मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए संबंधित फर्म से अधिसूचित कृषि उपज मक्का की कुल कीमत 8,34,900.00 रूपए पर दाण्डिक मण्डी शुल्क 41,745 रूपए (पांच गुना) समझौता शुल्क 5000 रूपए तथा निराश्रित शुल्क 8,349 रूपए (पांच गुना) कुल जुर्माना राशि 50,094 रूपए वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराये गये। उक्त कार्यवाही मण्डी समिति नैनपुर के उड़नदस्ता प्रभारी श्री गोपाल प्रसाद नीलवंशी (सहायक उप निरीक्षक) द्वारा संपादित किया गया।

कृषक जगत की सदस्यता हेतु संपर्क करें
शैलेन्द्र फरक्या, बलराम एंड ब्रदर्स, पिपलिया मंडी, जिला- मन्दसौर, मो. : 9893189345
सतीशचन्द्र शर्मा, मे. शर्मा एग्रो एजेन्सी, पनवाड़ी, जिला-शाजापुर, मो. : 9893296531
विशाल पाटीदार, मे. गायत्री कृषि एवं बीज भंडार, शुजालपुर मंडी, मो. : 8120700900

समस्या -समाधान

ड्रिप

समस्या : ड्रिप सिंचाई क्या है?

समाधान : ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल अथवा सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है और यह सर्वाधिक प्रभावी तकनीक है जिसमें फसल उत्पादन के लिए जल, उर्वरकों तथा अन्य पोषक तत्वों का कहीं अधिक प्रभावी उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य सिद्धान्त खेत में प्लास्टिक पाइप पर लगाये गये इमीटर्स की मदद से यथा संभव पौधे की जड़ के निकट जल तथा निवेशों का धीरे-धीरे, निरन्तर और बार-बार प्रयोग करना है।

लेजर लैण्ड लेवलिंग

समस्या : लेजर लैण्ड लेवलिंग के क्या लाभ हैं?

समाधान: जल अनुप्रयोग प्रभावशीलता में सुधार लाने और फसल की पैदावार को बढ़ाने में लेजर लैण्ड लेवलिंग एक आदर्श हस्तक्षेप है। वर्ष 2008 के दौरान कृषि विभाग के योजना तथा मूल्यांकन सेल द्वारा किए गए प्रभाव आकलन अध्ययन में इसके निम्नलिखित प्रभाव पाए गए :-सिंचाई के समय में 25.1 से 32.1 प्रतिशत तक की बचत। सिंचित क्षेत्रफल में 34.5 से 42.0 प्रतिशत तक की वृद्धि। फसल पैदावार में 10.7 से 12.9 प्रतिशत तक का सुधार। फार्म संवर्धन योग्य बंजर भूमि में 2.10 प्रतिशत तक की कमी। फसल को बेहतर ढंग से खड़े होने, एक समान नमी उपलब्धता और बढ़ी हुई उर्वरक उपयोग प्रभावशीलता की सुविधा।

सरसों

समस्या : सरसों की फसल में माहो के प्रकोप को कैसे नियंत्रित करें?

समाधान: सरसों में चेपा या माहू का प्रकोप दिसम्बर से जनवरी के माह में बादल वाले मौसम में अधिक होता है। इससे बचाव के लिए सरसों की बुआई मध्य अक्टूबर तक अवश्य करें। इससे फसल पर चेपा का कम प्रकोप होगा। यदि फिर भी प्रकोप होता है तो मैलाथियान दवा की एक लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 400-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

पपीता

समस्या : पपीते के बाग में नर-मादा पौधों को कैसे पहचाना जा सकता है?

समाधान: फूल निकलने से पहले नर और मादा पौधों को पहचाना नहीं जा सकता है। फूल निकलने के बाद पहचान यह है कि नर फूल लम्बी-लम्बी टहनियों (फूल वाली) के ऊपर अनेक संख्या में गुथे होते हैं। इस प्रकार की फूलों वाली टहनियां पत्तियां हैं। मादा फूल पत्तियों की काखों से अकेला-अकेला निकलता हैं और इसमें फल नुमा फूला हुआ भाग होता है।

पशु बीमा

समस्या : मेरे पास लगभग 35 पशु हैं, बीमा कराना चाहता हूं, मार्गदर्शन दें।

समाधान: पशुओं का बीमा 4 सरकारी बीमा कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दिनयू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करती है। जब भी कोई पशुपालक सरकारी योजना के अंतर्गत पशु खरीदता है तो उस पशु का बीमा उसी समय किया जाता है परंतु यदि कोई पशुपालक बगैर योजना के पशु रखता है तब उसे क्षेत्र के पशुचिकित्सक से पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाकर बीमा कंपनी में जमा कराना पड़ता है। पशु की कीमत का लगभग 3 प्रतिशत प्रीमियम कंपनी लेकर पशु का एक साल के लिए बीमा कर देती है। पशु के कान में कंपनी का टेग डाल दिया जाता है। पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को बीमा कंपनी में सूचना देनी होती है तथा पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराना होता है। दावा करने के बाद पशुपालक को बीमित राशि का भुगतान हो जाता है।

मूली

समस्या : सालभर क्या मूली की खेती करना संभव है, तकनीकी बतायें?

समाधान: विभिन्न मौसम में उगाई जाने वाली मूली की उन्नत किस्में, किस्म, बुआई का समय फसल तैयार होने का समय, उपज, पूसा देसी अगस्त के मध्य से अक्टूबर मध्य तक, मध्य सितम्बर से मध्य दिसम्बर तक, पूसा मृदुला सितम्बर के प्रथम पखवाड़े से मध्य नवम्बर तक अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से जनवरी के पहले खवाड़े तक, जेपनीज़ व्हाइट, पूसा स्वेता, पूसा जामुनी, पूसा गुलाबी दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े से फरवरी तक मध्य फरवरी से अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक, पूसा चेतकी अप्रैल के पहले सप्ताह से मध्य अगस्त तक मई के पहले पखवाड़े से सितम्बर के दूसरे पखवाड़े तक इन किस्मों को सालभर लगाया जा सकता है।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक रु. 95 कोड : 016
सब्जियों में पौध संरक्षण रु. 75 कोड : 017
मशरूम एक लाभ अनेक रु. 45 कोड : 019
मिर्च की उन्नत खेती रु. 55 कोड : 020
केला उत्पादन रु. 70 कोड : 025
गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण रु. 75 कोड : 027
पपीता रु. 55 कोड : 031
अदरक रु. 55 कोड : 032
फलों की खेती रु. 75 कोड : 040
सजाएं फूलों से बगिया रु. 65 कोड : 041
घर की बगिया रु. 95 कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/ मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 017 019 020 025 027 031 032 034 040 041 050

नाम
ग्राम पोस्ट तह.
जिला फोन/मोबा.
कुल राशि ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या
संलग्न ड्राफ्ट नं. मनी आर्डर रसीद क्र. वी.पी. भेजें

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

स्वास्थ्य

अक्षर नहीं पहचान पाना आंखों में रोग का संकेत

बच्चा अगर पढ़ने के दौरान अक्षरों को पहचानने में बार-बार गलती करता है तो इसके लिये उसकी आंखें जिम्मेवार हो सकती हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि आंखों में खराबी के कारण अक्षरों को पहचानने में समस्या आती है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि जब कोई बच्चा अक्षरों को सही-सही नहीं पहचान पाता तब इसको उसकी सीखने-समझने की क्षमता की कमी समझा जाता है। यह भी माना जाता है कि पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होने के कारण वह ऐसा करता है। पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यह समस्या केवल दिमागी विकास की कमी या पढ़ाने में रुचि न लेने की आदत का नतीजा नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अक्षर पहचानने में होने वाली परेशानी में मस्तिष्क की भूमिका ही नहीं होती। इसके लिए आंखें जिम्मेदार होती हैं, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जब आंखें गलत प्रतिबिंब बनाती हैं तब मस्तिष्क वस्तु का वास्तविक पहचान नहीं कर पाता।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान की दोनों आंखों की कोशिकाओं की बनावट भी अलग-अलग होती है। आम तौर पर इंसान की एक आंख ज्यादा, जबकि दूसरी आंख कम प्रभावशाली होती है। प्रभावशाली आंख में कोशिकाओं की बनावट गोलाकार होती है, जबकि दूसरी आंख की बनावट अंडाकार होती है। यही कारण है कि प्रभावशाली आंखें हमेशा सटीक तस्वीर मुहैया कराती हैं।

डिसलेक्सिया दिमागी बीमारी नहीं

डिसलेक्सिया को दिमागी बीमारी के रूप में देखा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। पर नए अध्ययन के मुताबिक, यह मस्तिष्क से नहीं, बल्कि आंखों की कोशिकाओं से जुड़ी बीमारी है। रॉयल सोसायटी के जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक, बच्चों में इस बीमारी के लिये उनकी आंखों की पुतली यानी रेटिना के भीतर की कोशिकाओं का असामान्य आकार जिम्मेवार हो सकता है।

दोनों आंखों का एक समान होना खतरनाक

जिन लोगों में डिसलेक्सिया होता है उनकी दोनों आंखों की कोशिकाओं की बनावट एक जैसी होती है। ये गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी। ऐसे में दोनों आंखों में प्रभावशाली होने की होड़ सी लगी रहती है। इस होड़ के चलते मस्तिष्क असमंजस में पड़ जाता है कि वह किस आंख की बनाई प्रतिबिंब ले और उसे आगे पहुंचाएं। शोधकर्ताओं के अनुसार, दोनों आंखों की इसी लड़ाई के चलते मस्तिष्क अक्षरों की सही जानकारी भी हासिल नहीं कर पाता, जिसके कारण अक्षर उलटे-पुलटे दिखाई पड़ते हैं।

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

- RO का पानी कभी ना पियें यह गुणवत्ता को स्थिर नहीं रखता। कुएँ का पानी पियें। बारिस का पानी सबसे अच्छा, पानी की सफाई के लिए सहिजन की फली सबसे बेहतर है।
- सोकर उठते समय हमेशा दायीं करवट से उठें या जिधर का स्वर चल रहा हो उधर करवट लेकर उठें।
- पेट के बल सोने से हर्निया, प्रोस्टेट, एपेंडिक्स की समस्या आती है।
- भोजन के लिए पूर्व दिशा, पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा बेहतर है।
- HDL बढ़ने से मोटापा कम होगा LDL व VLDL कम होगा।
- गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दें।
- चीनी के अन्दर सल्फर होता जो कि पटाखों में प्रयोग होता है, यह शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। चीनी खाने से पित्त बढ़ता है।
- शुक्रोज हजम नहीं होता है फ्रेक्टोज हजम होता है और भगवान की हर मीठी चीज में फ्रेक्टोज है ।
- वात के असर में नींद कम आती है।
- कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है।
- कफ के असर में पढ़ाई कम होती है।
- पित्त के असर में पढ़ाई अधिक होती है।
- आँखों के रोग-कैट्रेक्टस, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना आदि ज्यादातर रोग कफ के कारण होता है।
- शाम को वात-नाशक चीजें खानी चाहिए।
- प्रात: 4 बजे जाग जाना चाहिए ।
- सोते समय रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से कम होता है ।
- व्यायाम - वात रोगियों के लिए मालिश के बाद व्यायाम, पित्त वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए। कफ के लोगों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए।
- भारत की जलवायु वात प्रकृति की है, दौड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना चाहिए।
- जो माताएं घरेलू कार्य करती हैं उनके लिए व्यायाम जरुरी नहीं।
- निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु शांति होती है, उल्टी से कफ शांत होता है तथा उपवास से बुखार शांत होता है।
- भारी वस्तुयें शरीर का रक्तदाब बढ़ाती है, क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है।
- दुनिया के महान वैज्ञानिक का स्कूली शिक्षा का सफर अच्छा नहीं रहा, चाहे वह 8 वीं फेल न्यूटन हों या 9वीं फेल आइस्टीन हों।
- माँस खाने वालों के शरीर से अम्ल-स्राव करने वाली ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं।
- तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिए सिर्फ लकड़ी वाली घाणी का, दूध हमेशा पतला पीना चाहिए।
- छिलके वाली दाल-सब्जियों से कोलेस्ट्रोल हमेशा घटता है।
- कोलेस्ट्रोल की बढ़ी हुई स्थिति में इन्सुलिन खून में नहीं जा पाता है। ब्लड शुगर का सम्बन्ध ग्लूकोस के साथ नहीं अपितु कोलेस्ट्रोल के साथ है।
- मिर्गी दौरे में अमोनिया या चूने की गंध सूँघानी चाहिए।
- सिरदर्द में एक चुटकी नौसादर व अदरक का रस रोगी को सुंघायें।
- भोजन के पहले मीठा खाने से बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होता है।
- भोजन के आधे घंटे पहले सलाद खाएं उसके बाद भोजन करें।
- अवसाद में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस गुड़ और अमरुद में अधिक है।
- पीले केले में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है। हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस ज्यादा होता है तथा लाल केले में कैल्शियम कम आयरन ज्यादा होता है। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस होती है, वही हरी चीज पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमे कैल्शियम अधिक होता है।
- छोटे केले में बड़े केले से ज्यादा कैल्शियम होता है।
- रसौली की गलाने वाली सारी दवाएँ चूने से बनती हैं।
- हेपेटाइट्स A से E तक के लिए चूना बेहतर है।
- एंटी टिटनेस के लिए हाईपेरियम 200 की दो-दो बूंद 10-10 मिनट पर तीन बार दें।
- ऐसी चोट जिसमे खून जम गया हो उसके लिए नैट्रमसल्फ दो-दो बूंद 10-10 मिनट पर तीन बार दें। बच्चों को एक बूंद पानी में डालकर दें ।
- मोटापे में कैल्शियम की कमी होती है अत: त्रिफला दें। त्रिकूट (सोंठ+कालीमिर्च+मघा पीपली) भी दे सकते हैं।

कण-कण में व्याप्त हैं भगवान

भगवान कण-कण में विराजमान हैं। यह बौद्धिकता है, किंतु परमात्मा को प्रकट करना हार्दिकता है। तन के लिए जीतना भोजन आवश्यक है, मन के लिए भजन उतना ही आवश्यक है, जैसे बिना भूख के समय होने पर भोजन कर लेते हैं, वैसे ही मन न लगने पर समय से भजन करें। परमात्मा का मिलन संत की कृपा से होता है। राम-सुग्रीव का मिलन भगवान हनुमान जी जैसे संत ही करा सकते हैं। जब कोई काल से डरता है तो संत भगवान की स्मृति दिलाकर उसे निर्भय करते हैं। जब कोई भगवान से न डरे तो संत काल का भय दिखाकर उसमें भय उत्पन्न कर भगवान से जोड़ देते हैं। विभीषण ने हनुमान जी में भगवान को देखा। भक्ति विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। जैसे पानी में बिजली है, इसको जानकार बिजली पैदा करते हैं, यह विज्ञान है। कण-कण में परमात्मा विराजमान हैं। यह भाव ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से सूर्योदय होने से घोर कोहरा छंट जाता है, उसी प्रकार भक्ति से पाप कर्म धुल जाता है। कितनी ही धर्मार्थ यात्रा, गंगा स्नान, यज्ञ, धर्म, पाठ कर लें, किंतु एक भक्ति ही उसे अपने अधीन बना लेती है। सच्चे भक्त को कर्म-धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जिनके रोम-रोम में है, जिसके मुंह से सूर्य के समान ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनमें अनंत मात्रा का ऐश्वर्य हो, ऐसे श्रीकृष्ण ही हैं। उनकी हमें पांच भावों - शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की उपासना करनी चाहिए। इन सबमें श्रेष्ठ माधुर्य भाव ही है।

माधुर्य भाव ही सर्वाधिक सामिप्य है। इस भाव में हम प्रेयसी हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, ऐसी भावना निरंतर रहती है। अब लौकिक उदाहरण के अनुसार जैसे प्रेयसी का संबंध पति से अत्यंत निकट का होता है, पुत्र का उससे कम, सखा का उससे कम, दास का उससे भी कम तथा प्रजा का संबंध कम निकट का होता है। हमें भगवान श्रीकृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति करनी चाहिए।

पाक्षिक पंचांग

13 से 26 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत् 2082

कार्तिक कृष्ण 7 से कार्तिक शुक्ल 5 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
13	अक्टूबर	सोम	कार्तिक कृष्ण	7
14	अक्टूबर	मंगल	----------	8
15	अक्टूबर	बुध	----------	9
16	अक्टूबर	गुरु	----------	10
17	अक्टूबर	शुक्र	----------	11 रंभा एकादशी
18	अक्टूबर	शनि	----------	12 प्रदोष व्रत, धनतेरस
19	अक्टूबर	रवि	----------	13 शिव चतुर्थी व्रत
20	अक्टूबर	सोम	----------	14 दीपावली
21	अक्टूबर	मंगल	----------	30 स्ना.दा. अमावस्या
22	अक्टूबर	बुध	कार्तिक शुक्ल	1 गोवर्धन पूजा
23	अक्टूबर	गुरु	----------	2 भाई दोज
24	अक्टूबर	शुक्र	----------	3
25	अक्टूबर	शनि	----------	4 विनायकी चतुर्थी व्रत
26	अक्टूबर	रवि	----------	5 पांडव पंचमी

123certificates

सोपा का आह्वान

'सोया सीड क्रांति' के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं

इंदौर (कृषक जगत)। भारत को खाद्य तेल और प्रोटीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) ने देशव्यापी सोया सीड रेवोल्यूशन, शुरू करने का आह्वान किया है। इस पहल के तहत, उच्च उत्पादन क्षमता वाली, जलवायु-सहिष्णु सोयाबीन किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण किया जाएगा, ताकि देश के प्रत्येक किसान तक बेहतर बीज समयबद्ध तरीके से पहुँच सकें।

एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. डेविश जैन ने अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव 2025 में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारत की तेल और प्रोटीन आत्मनिर्भरता की नींव एक ही चीज पर टिकती है 'बीज क्रांति'। उन्होंने कहा, 'सोयाबीन केवल एक फसल नहीं, बल्कि किसानों की आशा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन और भारत की पोषण शक्ति है।

सोया उत्पादकता 1.1 टन प्रति हेक्टेयर

डॉ. जैन ने बताया कि वर्तमान में भारत की सोया उत्पादकता 1.1 टन प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत 2.6 टन प्रति हेक्टेयर से काफी कम है। सोपा का लक्ष्य है कि अगले पाँच वर्षों में उत्पादकता को 2 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुँचाया जाए और कम से कम 70 प्रतिशत किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाए। डॉ. जैन ने कहा, 'यदि हम प्रति हेक्टेयर सिर्फ 500 किलोग्राम की बढ़ोतरी भी कर लें, तो भारत अरबों रुपये के तेल आयात बचा सकता है और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।' भारत अपनी कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग रु. 1.7 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

सोयाबीन 'शक्ति का अन्न'

डॉ. जैन ने कहा कि इस निर्भरता को कम करने का सबसे टिकाऊ उपाय घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। सोयाबीन को 'शक्ति का अन्न' बताते हुए डॉ. जैन ने सरकार और खाद्य उद्योग से अपील की कि सोया फोर्टिफाइड आटा, सोया दूध, टोफू, और सोया स्नैक्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS), मिड-डे मील और पोषण अभियानों में शामिल किया जाए। इस दिशा में जागरूकता और नीति निर्माण के प्रतीक के रूप में, 2026 को 'सोयाबीन वर्ष' घोषित करने की उन्होंने जोरदार अपील की।

नॉन-जीएम उत्पादों की मांग

डॉ. जैन ने कहा कि सोयामील भारत के रु. 1.2 लाख करोड़ मूल्य के पोल्ट्री, मत्स्य और पशुपालन उद्योग की आधारशिला है। उन्होंने सस्ते विकल्पों जैसे DDGS के बढ़ते प्रयोग पर चिंता जताई, जो गुणवत्ता और पोषण को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत नॉन-जीएम (Non-GMO) सोया उत्पादों के लिए विश्व भर में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। डॉ. जैन ने कहा कि वैश्विक बाजार में नॉन-जीएम उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'दुनिया भारतीय सोया पर भरोसा करती है।

हमें इस भरोसे को पूंजी में बदलना है।' सोपा ने सरकार से पाँच वर्षीय लक्ष्य तय करते हुए सोया उत्पादकता वर्तमान में 1.1 से बढ़ाकर 2 टन प्रति हेक्टेयर का आह्वान किया। तीन वर्षों में 70 प्रतिशत किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाए, उत्पादकता तथा प्रसंस्करण क्षमता बढ़ा कर खाद्य तेल आयात में 25 प्रतिशत की कमी की जाए।

सलानेक्स : स्वस्थ फसल की आधारशिला

SML Transforming Agriculture

इंदौर (कृषक जगत)। देश की प्रसिद्ध कम्पनी एसएमएल लि. का नया सलानेक्स दुनिया का पहला पेटेंटेड दानेदार डीजी फार्मुलेशन वाला ऐसा उत्पाद है,जो न केवल अंकुरण से ही संतुलित पोषण की शुरुआत करता है, बल्कि लम्बे समय तक पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर स्वस्थ फसल की आधारशिला रखता है।

सलानेक्स ही क्यों ? : कम्पनी के हेड - क्रॉप न्यूट्रीशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट श्री अंजनी मनबंश ने सलानेक्स की बेहतरी के कई कारण गिनाते हुए बताया कि जैसे इसका डीजी फार्मुलेशन मिट्टी में सल्फर और ज़िंक के विघटन के साथ ही इन दोनों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में सहयोग करने से फसल,पोषण को जल्दी अवशोषित कर पाती है। वहीं इसकी एसआरटी तकनीक पौधे में अंकुरण से लेकर लम्बे समय तक पोषण सुनिश्चित करती है। अंकुरण से ही संतुलित पोषण मिलने एवं अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण होने से फसल स्वस्थ रहती है। इसका उपयोग इसलिए भी आसान है, क्योंकि सीड ड्रिल एवं अन्य बेसल उर्वरकों के साथ इसका प्रयोग करना अनुकूल है।

सलानेक्स के लाभ: दरअसल सलानेक्स, स्वस्थ एवं उत्पादक फसल के लिए एक मज़बूत आधार है, जिसके अनेक लाभ हैं। इसके प्रयोग से पौधों में एक समान स्वस्थ अंकुरण, पौधों में घनी जड़ों का विकास, फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार,क्षारीय मिट्टी के PH में सुधार होता है। इसके अलावा यह पौधों की आरम्भिक अवस्था में जैविक और अजैविक तनाव को सहने में भी मदद करता है। इन सब कारणों से स्वस्थ फसल से अच्छी उपज प्राप्त होने से किसानों की आय में वृद्धि होती है।

उपयोग विधि एवं मात्रा : सनालेक्स को अन्य उर्वरकों के साथ मिला सकते हैं। पंक्ति फसलों जैसे अनाज, तिलहन, दलहन आदि में सीड ड्रिल के माध्यम से बेसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनालेक्स का उपयोग बुआई से पहले अथवा बुवाई /रोपाई के समय करें।

प्रधानमंत्री ने किया महिंद्रा ट्रैक्टर्स कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन

मुंबई (कृषक जगत)। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में महिंद्रा ट्रैक्टर के कौशल विकास केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

भारत के नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड, महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने भारत के ग्रामीण कौशल और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग (डीवीईटी) और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी (एमएसएसडीएस) के साथ साझेदारी में गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज, गढ़चिरौली में इस कौशल विकास केंद्र की स्थापना की। नया केंद्र गढ़चिरौली के युवाओं को उद्योग-योग्य कौशल से लैस करने के साथ-साथ स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है।

गढ़चिरौली में ट्रैक्टर कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, महिंद्रा ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी में बेजोड़ उद्योग विशेषज्ञता के साथ-साथ उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता भी लाएगा। यह एक संरचित पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ है, जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है, जो ग्रामीण युवाओं को सबसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों तक पहुँच प्रदान करते हैं और ट्रैक्टर से संबंधित कौशल के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय के अध्यक्ष, श्री विजय नाकरा ने कहा, 'महिंद्रा में हम इस बात से बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गढ़चिरौली में महिंद्रा ट्रैक्टर कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र न केवल एक अग्रणी औद्योगिक केंद्र है, बल्कि एक ऐसा राज्य है जो कृषि क्षेत्र की विकास यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी करना हमारे लिए गर्व की बात है।'

श्री कुमार पुरुषोत्तम को पितृ शोक

भोपाल। मध्यप्रदेश कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के प्रबंध संचालक आईएएस श्री कुमार पुरुषोत्तम के पिता श्री सत्यदेव सिंह का गत 10 अक्टूबर को भोपाल में निधन हो गया। वे औरंगाबाद, बिहार के वेटनरी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया गया। उनके परिवार और मित्रों ने दुख की इस घड़ी में गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्री सिंह का जीवन सरलता, मिलनसार और मानवता के उच्चतम मानकों से भरा हुआ था। वे समाज में अपनी विनम्रता और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध थे। कृषक जगत परिवार मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).
नाम ....
....
ग्राम .... पो. ....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : ....
वि.ख. .... तह. ....
जिला .... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य ....
शिक्षा .... भूमि .... उम्र ....
ट्रैक्टर/मॉडल .... फोन/मो. ....
ई-मेल ....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये .... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. .... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

जनेकृविवि में नई नियुक्तियां

डॉ. अग्रवाल वानिकी विभाग के विभागाध्यक्ष बने

जबलपुर (कृषक जगत)। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की अनुशंसा पर कृषि महाविद्यालय, जबलपुर के वानिकी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं आचार्य डॉ. एस.बी.अग्रवाल बनाए गए हैं। डॉ. अग्रवाल ने जैविक खेती एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। आप उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जैसे कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किये जा चुके हैं। आपके 74 शोध पत्र, 3 पुस्तकें एवं कई तकनीकी बुलेटिन प्रकाशित हो चुके हैं।

डॉ. शर्मा बने संचालक विस्तार सेवाएं

जबलपुर (कृषक जगत)। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. पी. के. मिश्रा द्वारा उपकुल सचिव एवं उद्यानिकी के ख्यातिलब्ध प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. टी. आर. शर्मा को मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के संचालक का पद संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. टी. आर. शर्मा 3 दशक से अधिक कृषि विस्तार के क्षेत्र में अति उत्कृष्ट कार्य एवं अनुभव रखते हैं।

मूंगफली खरीदार का इंतजार...

ग्राम फिचला (कुरावन) तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर के किसान श्री गौरीलाल पिता श्री मांगीलाल बंजारा ढाई क्विंटल मूंगफली फसल मंदसौर कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए प्रयासरत हैं। दो बीघा में ढाई क्विंटल पैदावार का दाम मंडी में 4 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल मिलने की संभावना है।

दलौदा एग्री एम्प्लाईज एसोसिएशन की बैठक सम्पन्न

मन्दसौर (कृषक जगत)। 'संगठन में शक्ति' का भाव जगाने के लिए जिले की दलौदा तहसील में भी एग्रीकल्चरल एम्प्लाईज एसोसिएशन की वार्षिक बैठक का बंजारी बालाजी तीर्थ पर आयोजन किया गया। विभिन्न खाद, बीज, कीटनाशक कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे संगठन के सदस्यों ने कंपनी और कृषि आदान विक्रेता के साथ ही किसानों के बीच बेहतर तालमेल बैठाकर इस व्यवसाय को और बेहतर स्थापित करते हुए सदस्यों ने अपनी बात रखी। बैठक में सभी ने अपना परिचय देते हुए कृषि आदान व्यवसाय में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। संगठन के सदस्य श्री श्याम दास रामावत ने सभी से आग्रह किया कि वे बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन ना चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। सदस्यों का समूह बीमा, परिचय पत्र आदि मांगों पर विचार किया गया। बैठक में सदस्य सर्वश्री अरविंद सिंह, बृजेश पवार, सुरेश मीणा, राजेन्द्र सिंह, अरविंद पाटीदार ने अपने विचार रखें। लगभग 75 सदस्यों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।

नरवाई प्रबंधन के लिए श्री मालवीय पहुंचे खेतों में

बालाघाट (कृषक जगत)। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान उत्पादन के बाद शेष बचे अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग उसके प्रबंधन पर किसानों का अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहा है। जिले के उपसंचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय सतत् दौरा कर किसानों के बीच खेतों में पहुंचकर नरवाई जलाने के नुकसान बता रहे हैं।

कृषि विभाग ने धान की नरवाई जलाने से रोकने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। नरवाई प्रबंधन के लिए हैप्पी, सुपर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिलेज आदि मशीनों का उपयोग बढ़ाने का प्रचार-प्रसार के साथ ही नरवाई जलाने पर होने वाले नुकसान बताए जा रहे हैं। विभाग ने जिले में इस वर्ष नरवाई प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान चलाया है इसके तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं किसान चौपाल, खेत पाठशाला, कृषि संगोष्ठी, जी फार्म ऐप डाउनलोड, वर्तमान में इस ऐप से लगभग 36 हजार किसान जुड़े, विभागीय अधिकारी, पटवारी, कोटवार की मुनादी, दण्डात्मक कार्यवाही की समझाइश दी।

पटवारी एग्रो एजेन्सी
:: वितरक ::
◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि. ◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि. ◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ ◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया ◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.
17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

कैरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि., खरगोन
आपकी समृद्धि हमारी प्राथमिकता
हमारे यहां पर ड्रिप में फ्लैट और राउण्ड एचडीपीई व स्प्रिंकलर पाईप, एचडीपीई क्वाइल, लपेटा पाईप एवं रेन पाईप वर्जिन एवं उच्च क्वालिटी में बनाये जाते हैं। **सम्पर्क** - निरंजन नगर, कसरावद रोड, खरगोन,
मो. : 7880017028, 7880017021 मई 25

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेराग्लेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर
ODOP - मिर्च-खरगोन
निमाड़फ्रेश FPO (JV) हरिओम भुरे 8964087240
टेराग्लेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408
जुलाई 26

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी
ISO 9001 : 2015 सर्टिफाईड
किसान हाईटेक ग्रीनहाऊस नर्सरी
द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पत्तागोभी, फूलगोभी आदि सब्जी के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। **संपर्क : मो. :** 9407853117, 9407853118, 9407853119, **नर्सरी स्थल : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)**
मार्च 25

मध्यभारत की सबसे बड़ी नर्सरी
तिरुपति ग्रीन हाऊस नर्सरी
देश का सबसे बड़ा पौध भंडार औषधीय, फलदार, सजावटी फूलों के पौधे, इनडोर, टिश्यूकल्चर, क्रीपर, बोन्साई, सक्यूलेन्ट्स, केक्टस, हैंगिंग प्लांट, वर्टीकल प्लांट, लकी बैंबू रेंज, फॉरेस्ट्री प्लांट एवं सब्जियों के पौधों की विस्तृत श्रृंखला में
: आपका स्वागत है :
सिरलाय (बड़वाह) मध्यप्रदेश
www. tirupatinursery.com
email : tirupatinursery@gmail.com
मो. : 9479457720/99/63/86/96/16/17/13/31/51
मार्च 2025

कई प्रकार की फसलों के लिए एकमात्र स्वचलित गियर ड्राईव
वरदान
मल्टीक्रॉप पॉवर रीपर
वरदान एग्री सॉल्यूशन्स प्रा.लि.
63, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452015 (म.प्र.) फोन: 0731-4970600, 6264916090.

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ
व्यक्तिगत क्लासीफाइड
विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ▪ बीज ▪ औषधीय फसल
विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ▪ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड
विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5% अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

'समुन्नति एफपीओ कॉन्क्लेव 2025'

साझेदारी से मजबूत होते किसान उत्पादक संगठन

Samunnati

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 5वां समुन्नति एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 सितंबर माह में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समुन्नति और नाबार्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

इस कॉन्क्लेव में देशभर के किसान संगठनों, कृषि-उद्योगों और नवाचारकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य साझेदारी के ज़रिए भविष्य के लिए तैयार एफपीओ पारितंत्र को मज़बूत बनाना था। हैदराबाद में 3-4 सितम्बर को हुए दो दिवसीय कॉन्क्लेव का विषय था - 'सस्टेनेबिलिटी के लिए साझेदारी: भविष्य के लिए तैयार एफपीओ पारितंत्र की ओर।'

इसमें देशभर से 2,500 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 एफपीओ नेता, 300 पारिस्थितिकी भागीदार और 100 स्टार्टअप्स व कृषि उद्यम शामिल हुए।

एफपीओ आंदोलन को मिली नई दिशा

एफपीओ कॉन्क्लेव का मकसद सिर्फ चर्चा करना नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करना था। इस साल का सम्मेलन दिखाता है कि अब एफपीओ नीतिगत मंचों से आगे बढ़कर ग्रामीण विकास के मज़बूत व्यावसायिक केंद्र बन रहे हैं।

कार्यक्रम में 'स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट - एफपीओ 2025' जारी की गई, जिसे नेशनल एसोसिएशन फॉर एफपीओ (NAFPO) ने तैयार किया है।

इस रिपोर्ट में भारत के 44,000 से अधिक एफपीओ का विश्लेषण किया गया है और 'Ease of Doing Business for FPOs Index' के ज़रिए बताया गया है कि कौन से राज्य एफपीओ के विकास के लिए सबसे बेहतर माहौल प्रदान कर रहे हैं।

इसके पूर्व उद्घाटन सत्र में समुन्नति के संस्थापक और सीईओ श्री अनिल कुमार एस.जी. ने कहा कि भारत की कृषि में बड़ी संभावनाएँ हैं, जिन्हें साझेदारी और नवाचार के ज़रिए ही साकार किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार एफपीओ को ग्रामीण समृद्धि का प्रमुख इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समुन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा ने कहा कि एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से मजबूत हो रहा है, जो रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। उन्होंने प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे ऐसा भविष्य बनाएं, जहाँ सामूहिक उद्यम, नवाचार और बेहतर बाजार संपर्क देश के लाखों छोटे किसानों के जीवन में सुधार लाएं। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा कि कृषि का भविष्य जलवायु-संवेदनशील, सामूहिक और बाज़ार-केंद्रित ढांचे में है।

ग्राम हाट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक

आईटीसी लि. में कृषि एवं आईटी समूह प्रमुख श्री शिवकुमार ने एक विशेष फायरसाइड सत्र में कहा कि कृषि-विपणन पारंपरिक हाट से आगे बढ़कर अब डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि आईटीसी प्रौद्योगिकी आधारित स्थायी मूल्य श्रृंखलाओं और एफपीओ के साथ सहयोगात्मक बाजार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शिवकुमार ने समावेशी विकास और किसान सशक्तिकरण को कंपनी की प्रमुख रणनीति बताया। वहीं सह्याद्री फार्म्स के श्री विलास शिंदे, कोर्टेवा एग्रीसाइंस के श्री सुब्रतो गीड और ओलम ग्रुप के श्री एन. मुत्थुकुमार ने मूल्य श्रृंखला के एकीकरण, विज्ञान-आधारित नवाचार और जलवायु-स्मार्ट कृषि पर अपने विचार साझा किए। समापन सत्र में समुन्नति के चेयरमैन श्री एन. श्रीनिवासन ने कहा, 'एफपीओ कॉन्क्लेव केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों को केंद्र में रखकर बाजार, वित्त और नवाचार को जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता है।'

इसके साथ ही, समुन्नति और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'बिल्डिंग एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर इंडियन FPOs' भी जारी की गई।

इसमें बताया गया है कि वित्त, बाज़ार, तकनीक और सलाहकारी सेवाओं की बेहतर पहुँच से एफपीओ को मजबूत और निवेश योग्य संस्थाओं में बदला जा सकता है।

एफपीओ स्केलएक्स प्रोग्राम की शुरुआत

कॉन्क्लेव की सबसे बड़ी घोषणा रही 'एफपीओ स्केलएक्स' कार्यक्रम की शुरुआत। इसका लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 300 एफपीओ को रू. 100 करोड़ क्लब में पहुँचाया जाए, जिन्हें 'यूनिकॉर्न एफपीओ' कहा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन एफपीओ को टिकाऊ, मज़बूत और बाज़ार में अग्रणी संस्थाओं के रूप में विकसित करना है।

इसी दौरान पीएफआरडीए (PFRDA) के कार्यकारी निदेशक ने किसानों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जोड़ने पर ज़ोर दिया और इसे किसानों के लिए 'दूसरी फसल' बताया, जो ग्रामीण परिवारों को लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा देगी।

नेताओं ने रखी कृषि के भविष्य की रूपरेखा डिजिटल कृषि की दिशा में बड़ा कदम - यूकेआई पहल

कॉन्क्लेव के दौरान आरती इंडस्ट्रीज़ के श्री मिरिक गोगरी और यूकेआई के श्री अनुराग दीक्षित ने समुन्नति के साथ यूनिफाइड कृषि इंटरफेस (UKI) की घोषणा की, जो किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों को बीज, खाद, सलाह, तकनीकी सेवाओं और उपकरणों तक एक ही माध्यम से पहुँच देगा ।यह परियोजना फिलहाल नासिक में पायलट चरण में है ।

खेत से आई प्रेरक कहानियाँ

कॉन्क्लेव के विशेष सत्र 'इनसाइट्स फ्रॉम द फील्ड' में दो किसानों के नेतृत्व वाले संगठनों की कहानियाँ विशेष आकर्षण रहीं। नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफपीओ के संस्थापक श्री पुनीत सिंह थिंद और मिष्टि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक श्री संजीव ने बताया कि कैसे सामूहिक उद्यम से किसानों की आय, बाजार पहुँच और संस्थागत क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन उदाहरणों ने यह दिखाया कि संगठित प्रयास और नवाचार मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व और ताकत दे सकते हैं।

कृषि परिवर्तन का साझा मंच

कॉन्क्लेव के दौरान नाबार्ड पैवेलियन में देशभर के एफपीओ ने अपने उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी में स्टार्टअप्स, कंपनियाँ और वित्तीय संस्थाएँ भी शामिल रहीं, जिसने इस आयोजन को एक जीवंत सहयोग मंच में बदल दिया। राष्ट्रीय कृषि अखबार कृषक जगत इस कॉन्क्लेव का मीडिया पार्टनर रहा। कॉन्क्लेव के समापन पर यह संदेश स्पष्ट था- एफपीओ का विकास ही भारत के कृषि परिवर्तन की धुरी है। समुन्नति एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 ने यह दिखाया कि जब साझेदारी, नवाचार और समावेशिता एक साथ आती हैं, तो भारत का ग्रामीण परिदृश्य न केवल आत्मनिर्भर बल्कि भविष्य के लिए तैयार बनता है।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
शुभ
लाभ
Coromandel
FUTURE POSITIVE
ग्रोमोर
जिनके भरोसे दुनिया,
उनका भरोसा ग्रोमोर
GROMOR
क्योंकि हम किसान जानते हैं,
सब हमारे भरोसे हैं,
इसलिए हमारा भरोसा!
GROMOR
GROMOR
GROALPHA
Gro+Plus